साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार 13-19 जून 2022, वर्ष-8, अंक-10

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

फैसले से किसानों की बढ़ेगी आय, किसानों को अधिक रियायती दरों पर खाद उपलब्ध कराने बढ़ सकती है सब्सिडी

केंद्र सरकार ने खरीफ की फसलों की बढ़ाई एमएसपी

नई दिल्ली।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2022-23 के लिए विभिन्न खरीफ (गर्मी) फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी है। इससे फसल वर्ष 2022-23 के लिए खरीफ फसलों का एमएसपी अब बढ़ जाएगा। किसानों को इससे काफी फायदा होगा। धान की सामान्य ग्रेड किस्म के लिए एमएसपी को पिछले वर्ष के 1,940 रुपये से बढ़ाकर 2,040 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। वहीं, धान की 'ए' ग्रेड किस्म का समर्थन मूल्य 1,960 रुपये से बढ़ाकर 2,060 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। खरीफ की प्रमुख फसल धान होती है, जिसकी बुवाई शुरू हो चुकी है।

फसल	पिछला एमएसपी	प्रस्तावित एमएसपी	बढ़ोत्तरी
धान(सामान्य)	1940	2040	100
धान(ग्रेड ए)	1960	2060	100
अरहर	6300	6600	300
मूंग	7275	7755	480
उड़द	6300	6600	300
कपास	5726	6080	354
कपास	6025	6325	300
सोयाबीन	3950	4300	350
सूरजमुखी	6015	6400	385
मूंगफली	5550	5850	300
तिल	7307	7830	523
नाइजर सीड	6930	7287	357
मक्का	1870	1962	92
रागी	3377	3578	201

तीन वर्षों में खरीफ खाद्यान्न उत्पादन में औसतन 2.8 प्रतिशत की वृद्धि

पिछले तीन वर्षों में सामान्य से अच्छे मानसून के चलते खरीफखाद्यान्न उत्पादन में औसतन 2.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और इसके परिणामस्वरूप खरीफउत्पादन में 2.5 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है।

बढ़ेगी किसानों की आय

इससे पहले एक विदेशी ब्रोकरेज रिपोर्ट में कहा गया है कि खरीफ कृषि आय में लगातार दूसरे वर्ष मजबूत वृद्धि की उम्मीद है। हालांकि, वैश्विक स्तर पर उर्वरक और फीड की कीमतें बढ़ने से खरीफ कृषि लागत में और वृद्धि होने की उम्मीद है। पिछले महीने, सरकार ने जोर देकर कहा कि मौजूदा खरीफ सीजन के दौरान उर्वरकों की उपलब्धता अनुमानित मांग से अधिक है। साथ ही सरकार ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष के लिए ऊर्वरक पर सब्सिडी बढ़कर लगभग 2.5 लाख करोड़ हो सकती है, ताकि किसानों को अत्यधिक रियायती दरों पर खाद मिल सके।

अब उद्योंगों में जमीन देकर पार्टनर बनेंगे किसान

अब उद्योंगों में जमीन देकर पार्टनर बन सकेंगे किसान

भोपाल। संवाददाता

प्रदेश के किसानों को अब जमीन के बदले पर्याप्त मुवाबजे के साथ उनकी जमीन पर लगने वाले उद्योग में हिस्सेदारी भी मिलेगी। लैंड पूलिंग के इस नए माडल को मप्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी है। लैंड पूलिंग के इस माडल को देश का अनूठा माडल बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट की बैठक में सरकार ने फैसला किया है कि अतिक्रमणकारियों माफिया और कब्जों से मुक्त कराई जमीनों पर गरीबों के लिए घर बनाए जाएंगे। इन जमीनों पर स्कूल भी खोले जाएंगे। कैबिनेट की बैठक के बाद गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जो भूमि दबंगों, भूमाफिया और अतिक्रमणकारियों से छुड़ाई गई है, उसे गरीबों को आवास के लिए, आंगनबाड़ी और स्कूलों के लिए दिया जाएगा।

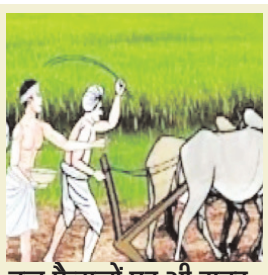

इन फैसलों पर भी मुहर

इंदौर- पीथमपुर निवेश क्षेत्र में किसानों की सहमति से लैंड पूलिंग स्कीम के अंतर्गत 500 हेक्टेयर भूमि लिए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। कैबिनेट ने भोपाल के अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र मे बहुउत्पाद कंपनियों को भू-खड़ दिए जाने का निर्णय किया है। महिला उद्यमियों को उद्योग स्थापना के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। शिवराज कैबिनेट ने दतिया जिले में 330 1560 रुपए बढ़ाकर 2000- मेगावॉट की सौर ऊर्जा परियोजना रुपए कर दिया गया है। लगाने की अनुमति प्रदान की है।

किसानों के खेतों में दौड़ेंगे इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, जानिए क्या है प्लान

नई दिल्ली, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि,वह जल्द ही भारत में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर और ट्रक लॉन्च करने की तैयारी में हैं। गडकरी ने कहा कि सरकार वैकल्पिक ईंधन और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देगी। उन्होनें कहा कि, जल्द ही मैं एक इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर और इलेक्ट्रिक ट्रक लॉन्च करूंगा, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की लोकप्रियता कई गुना बढ़ जाएगी। गडकरी ने कहा कि बजाज, टीवीएस और हीरो ने इलेक्ट्रिक बाइक पेश की हैं, और इलेक्ट्रिक रिक्शा भी सड़कों पर हैं। उन्होंने कहा कि 2025 तक ऑटोमोबाइल उद्योग का कुल कारोबार मौजूदा 6.5 लाख करोड़ रुपये से लगभग 15 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। गडकरी ने कहा कि कृषि उपकरणों को फ्लेक्स इंजन में बदलने के प्रयास किए जाने चाहिए। इससे कृषि क्षेत्र में भी डीजल पर निर्भरता कम होगी और खर्च पर भी नियंत्रण होगा। हालांकि गडकरी ने आने वाले इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की है। हाल ही में नितिन गडकरी देश के ऑटो इंडस्ट्री को पारंपरिक फ़्यूल (पेट्रोल-डीजल) के बजाय इथेनॉल, मेथनॉल, ग्रीन हाइड्रोजन और अन्य ईंधन विकल्पों वाले वाहनों के निर्माण पर जोर देने को कहा था। गडकरी के इस बयान ऑटो इंडस्ट्री ने स्वागत भी किया और नए फ़्यूल वाले वाहनों पर काम शुरू करने की अपनी मंशा भी जाहिर की थी। उन्होनें एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा था कि, मैं ऑटोमोबाइल उद्योग में सभी से अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया आप संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और कनाडा की तरह फ्लेक्स इंजन लाने में हमारा सहयोग करें। उन्होनें कहा कि, मैं मानता हूं कि, चारपहिया या दोपहिया दोनों तरह के वाहन पेट्रोल या इथेनॉल फ्यूल से आसानी से चल सकते हैं।

इंदौर ने प्राप्त किया सर्वोच्च स्थान

खाद्य सुरक्षा पहल के लिए मप्र के आठ जिलों को मिला ईट-राइट चैलेंज पुरस्कार

भोपाल। संवाददाता

मध्यप्रदेश के 8 जिलों- इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर और सतना को आज एफडीए भवन में कार्यक्रम में ईट-राइट चैलेंज फॉर सिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट्स के तहत खाद्य सुरक्षा को लेकर सकारात्मक परिर्वतन के लिये सम्मानित किया गया। इंदौर, जबलपुर, सागर और उज्जैन को ईट-स्मार्ट सिटीज चेलेंज में शीर्ष 11 स्मार्ट सिटी में स्थान प्राप्त करने पर पुरस्कृत किया गया। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर कार्यक्रम में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया द्वारा पुरस्कार वितरित किये गये। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण एवं भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरूण सिंघल भी उपस्थित थे।

75 शहर और जिले बने विजेता

ईट-राइट चैलेंज फॉर सिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट्स के तहत खाद्य सुरक्षा की पहलों को अपनाने, नियम और परिवर्तन को बढ़ावा देने के प्रयासों को मान्यता देने के उद्देश्य से देश के 75 शहरों और जिलों को विजेता चुना गया है। इस स्पर्धा में देश के 188 शहरों ने अपना पंजीकरण किया था, जिनमें से सर्वोच्च अंकों के साथ इंदौर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भोपाल, उज्जैन, जबलपुर ने क्रमशः 3, 5 और 7वां स्थान प्राप्त किया है। ग्वालियर को 12वां, रीवा को 17वां, सागर को 23वां और सतना को 74वां स्थान प्राप्त हुआ है। पुरस्कार खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. सुदाम खाड़े द्वारा ग्रहण किये गये।

भोजन दान करने की नीति के लिये इंदौर स्मार्ट सिटी को पुरस्कार

ईट-स्मार्ट सिटीज चेलेंज के तहत घरेलू स्तर पर रिसाइक्लिंग और अतिशेष भोजन दान करने की नीति के लिये इंदौर स्मार्ट सिटी को पुरस्कृत किया गया, जिसका पुरस्कार अतिरिक्त कलेक्टर अभय बेडेकर ने ग्रहण किया। जबलपुर स्मार्ट सिटी को बच्चों में मोटापे की समस्या से निपटने के लिये कार्टून किरदारों द्वारा व्यवहार परिवर्तन को लेकर शुरू की गई पहल के लिये सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार स्मार्ट सिटी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधि सिंह राजपूत ने ग्रहण किया। सागर स्मार्ट सिटी द्वारा बच्चों को खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण देने के लिये विडियो गेम और युवा पोषण एम्बेसेडर तैयार करने के लिये पुरस्कृत किया गया। सागर स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल सिंह राजपूत ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। हाइड्रोपोनिक्स को बढ़ावा देने के लिये उज्जैन स्मार्ट सिटी को पुरस्कृत किया गया, जिसका पुरस्कार उज्जैन स्मार्ट सिटी के कार्यकारी निदेशक अंशुल गुप्ता द्वारा ग्रहण किया गया।

बेंची गई फसल का भुगतान न होने से जमा नहीं कर पाए हैं ऋण की राशि

12 लाख किसानों को डिफाल्टर होने से बचाने में जुटी सरकार

भोपाल। संवाददाता

प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से अल्पावधि कृषि ऋण लेने वाले किसानों को डिफाल्टर होने से बचाने का रास्ता निकालने में सरकार जुट गई है। दरअसल, खरीफ सीजन 2021 का ऋण चुकाने की अंतिम अवधि 28 मार्च 2022 थी, जिसे सरकार ने बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दिया था। किसानों ने समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना, मसूर और सरसों सरकारी उपार्जन केंद्रों पर बेची, पर उसका भुगतान अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इस कारण किसान ऋण अदायगी समय पर नहीं कर पाए और डिफाल्टर हो गए। डिफाल्टर किसानों की संख्या लगभग 12 लाख है। प्रदेश में प्रति वर्ष सहकारी समितियों के माध्यम से 35 लाख से अधिक किसान शिवराज सरकार की ब्याज रहित अल्पावधि कृषि ऋण योजना का लाभ लेते हैं। इसके तहत खरीफ और रबी फसलों के लिए ऋण दिया जाता है। खरीफ फसल का ऋण 28 मार्च और रबी फसल का ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 15 जून रहती है। सरकार ने इस बार खरीफ फसल का ऋण चुकाने की अवधि 28 मार्च से बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दी थी।

इसके बाद भी रिकवरी सभी 38 जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों की 15 अप्रैल 2022 तक 35.41 प्रतिशत ही रही। इसमें अवधि वृद्धि से 6.69 प्रतिशत रिकवरी ही और बढ़ी। बैंकों को किसानों से कुल 19 हजार 417 करोड़ रुपये लेने हैं। किसानों को डिफाल्टर होने से बचाने के लिए सरकार ने ब्याज माफी देने की घोषणा भी की है। इसमें किसानों को मूलधन चुकाना है। इस योजना का खाका तैयार किया जा रहा है। उधर, खरीफ फसल के लिए जिन किसानों ने ऋण लिया था, वे भी डिफाल्टर न हो जाएं, इसके लिए ऋण अदायगी की तारीख बढ़ाई गई थी, लेकिन किसानों को समर्थन मूल्य पर उपज बेचने के बाद भी अब तक पूरा भुगतान नहीं मिल पाया है।

सीएम ने कोई रास्ता निकालने दिया निर्देश

उल्लेखनीय है कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग ने चार लाख 90 हजार किसानों का भुगतान किया है, जबकि पांच लाख 72 हजार 154 किसानों ने 44 लाख 45 हजार 937 टन उपज बेची है। इसी तरह एक लाख से अधिक किसान समर्थन मूल्य पर चना बेच चुके हैं। यह राशि किसानों के खातों में जमा नहीं हो पाई, नतीजा ऋण राशि का समायोजन नहीं हो पाया और किसान सहकारी बैंकों के प्रविधान के अनुसार डिफाल्टर हो गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बैठक में यह मुद्दा उठा तो उन्होंने इसका रास्ता निकालने के निर्देश दिए।

सहकारिता विभाग ने निकाला रास्ता

सूत्रों के मुताबिक सहकारिता विभाग ने किसानों को डिफाल्टर होने से बचाने के लिए यह रास्ता निकाला है कि जिन किसानों ने समर्थन मूल्य पर उपज बेच दी है और भुगतान नहीं हुआ है, उन्हें डिफाल्टर नहीं माना जाएगा। ऐसे किसान पंजीयन की तारीख से आगामी सीजन के लिए ऋण लेने के पात्र माने जाएंगे। फायदा यह होगा कि किसानों को समितियों से खाद-बीज के साथ नकद राशि भी पात्रता के अनुसार ब्याज रहित ऋण योजना के अंतर्गत मिल जाएगी। हालांकि, समितियों को ऋण अदायगी की अंतिम तिथि बढ़ाने और जब तक राशि नहीं मिल जाती है, उस दौरान का ब्याज सरकार को वहन करना होगा। बता दें कि अंतिम तिथि बढ़ाने से सरकार पर 70 करोड़ रुपये का भार आया था।

मप्र सरकार की बढ़ी चिंता, सीएम ने लिखा पत्र

सिर्फ सवा दो लाख टन मूंग खरीदेगा केंद

प्रदेश में उत्पादन का अनुमान 11 लाख टन से अधिक है

भोपाल। संवाददाता

मध्य प्रदेश में तीसरी फसल के रूप मं ग्रीष्मकालीन मूंग का क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वर्ष सवा नौ लाख हेक्टेयर में किसानों ने मूंग की फसल ली। समर्थन मूल्य पर इसका उपार्जन होना है। केंद्र सरकार ने प्राइस सपोर्ट स्कीम में दो लाख 25 हजार टन मूंग खरीदने का लक्ष्य मध्य प्रदेश के लिए निर्धारित किया है, जबकि उत्पादन का अनुमान 11 लाख टन से अधिक है। इस हिसाब से जो लक्ष्य मिला है वो बेहद कम है। इसने सरकार को चिंता में डाल दिया है, इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर को पत्र लिखकर लक्ष्य बढ़ाने का अनुरोध किया है।

पिछले वर्ष चार लाख टन मूंग खरीदी गई थी

प्रदेश में पिछले साल चार लाख टन ग्रीष्मकालीन मूंग समर्थन मूल्य पर खरीदी गई थी। इसका फायदा यह हुआ था कि बाजार में मूंग की कीमत समर्थन मूल्य से अधिक या उसके आसपास रही। सरकार चाहती है कि इस बार भी किसानों को उपज का वाजिब दाम मिले। मूंग का समर्थन मूल्य सात हजार 275 रुपये प्रति क्विंटल है। जबकि, बाजार में मूंग की कीमत प्रति क्विंटल छह हजार रुपये के आसपास है।

...तो किसानों को होगा नुकसान

इस प्रकार देखा जाए तो यदि समर्थन मूल्य पर उपार्जन का लक्ष्य नहीं बढ़ता है तो किसानों को आर्थिक नुकसान होगा। हरदा, होशंगाबाद, सीहोर, नरसिंहपुर, रायेसन जिले में पांच लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में मूंग की फसल बोई गई है। इसे देखते हुए सरकार ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि उपार्जन का लक्ष्य बढ़ाया जाए। पिछले साल भी केंद्र सरकार ने एक लाख 39 हजार टन मूंग खरीदने का लक्ष्य दिया था, जिसे मुख्यमंत्री के अनुरोध पर बढ़ाकर दो लाख 47 हजार टन किया था। हालांकि, खरीदी चार लाख टन की हुई थी और इसका वित्तीय भार राज्य सरकार को उठाना पड़ा था। हाल ही में लगभग सात सौ करोड़ रुपये की मूंग सरकार ने मध्या- भोजन योजना में विद्यार्थियों को वितरित कराई है।

जमीन और फसल के लिए अमृत है जीवामृत, जानें कैसे बनाएं

जमीन और फसल के लिए अमृत है जीवामृत, जानें कैसे बनाएं

भोपाल। संवाददाता

समय परिवर्तन के साथ हमने विकास की होड में अपनी प्राचान परंपराएं और कृषि पद्धतियों को भुला दिया । पिछले कुछ वर्षों में, किसानों ने जैविक खाद की उपेक्षा रासायनिक उर्वरक पर ध्यान केंद्रित किया है जो मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। हमारी इस भूल का परिणाम है कि रसायनिक दुस्प्रभाव के चलते कई प्रकार की बीमारिया और ब्याथियां लोगों को घेर रहीं हैं। अब जरूरी हो गया है कि हम जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर मुडें। जैविक खेती में जीवामृत का विशेष महत्व है। जीवामृत को हम कम खर्च में अपने घर में स्वयं ही बना सकते हैं, जो हमारी फसल और हमारे स्वाथ्य के लिए भी अनुकूल होगा। जीवामृत के प्रयोग से जहां एक तरफ हमारी खेती की जमीन अच्छी होगी तो दूसरी तरफ उत्पादन में भी वृद्धि देखने को मिलेगी।

जीवामृत से निकलते हैं चमत्कारी परिणाम- एक एकड़ जमीन के लिए 10 कि.ग्रा. गोबर के साथ गोमूत्र, गुड़ और दो-दले बीजों का आटा या बेसन आदि मिलाकर प्रयोग में लाने से चमत्कारी परिणाम निकलते हैं। इस जीवामृत विधि से पूरे भारत में लाखों किसान लाभान्वित हुए हैं।

जीवामृत की सामग्री (आचार्य देवव्रत जीवामृत)

- देशी गाय का गोबर 10 कि.ग्रा.
- देशी गाय का मूत्र 8-10 लीटर
- गुड़ 1-2 कि.ग्रा.
- बेसन 1-2 कि.ग्रा.
- पानी 180 लीटर
- पेड़ के नीचे की मिट्टी 1 कि.ग्रा.

जानिए कैसे बनाएं जीवामृत

उपरोक्त सामग्रियों को प्लास्टिक के एक ड्रम में डालकर लकड़ी के एक डंडे से घोलना है और इस घोल को दो से तीन दिन तक सडने के लिए छाया में रख देना है। प्रतिदिन दो बार सुबह-शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी के डंडे से दो मिनट तक इसे घोलना है और जीवामृत को बोरे से ढक देना है। इसके सडने से अमोनिया, कार्बन डाईआक्साइड, मीथेन जैसी हानिकारक गैसों का निर्माण होता है। गर्मी के महीने में जीवामृत बनने के बाद सात दिन तक उपयोग में लाना है और सर्दी के महीने में 8 से 15 दिन तक उसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद बचा हुआ जीवामृत भूमि पर फेंक देना है।

वैज्ञानिक शोध में सामने आया आश्चर्यजनक परिणाम

दिसम्बर महीने में तैयार किए गए जीवामृत पर एक वैज्ञानिक द्वारा शोध किया गया, जिसमें जीवामृत तैयार करने से 14 दिन बाद सबसे अधिक 7400 करोड़ जीवाणु (बैक्टीरिया) पाए गए। इसके बाद इसकी संख्या घटनी शुरु हो गई। गुड़ और बेसन दोनों ने ही जीवाणुओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गोबर, गोमूत्र व मिट्टी के मेल से जीवाणुओं की संख्या केवल तीन लाख पाई गई। जब इनमें बेसन मिलाया गया तो इनकी संख्या बढ़कर 25 करोड़ हो गई और जब इन तीनों में बेसन की जगह गुड़ मिलाया गया तो इनकी संख्या 220 करोड़ हो गई, लेकिन जब गुड़ व बेसन दोनों ही मिलाया गया अर्थात जीवामृत के सारे घटक (गोबर, गोमूत्र, गुड़, बेसन व मिट्टी) मिला दिए गए तो आश्चर्यजनक परिणाम सामने आए और जीवाणुओं की संख्या बढ़कर 7400 करोड़ हो गई। यही जीवामृत जब सिंचाई के साथ खेत में डाला जाता है तो भूमि में जीवाणुओं की संख्या अविश्वसनीय रूप से बढ़ जाती है और भूमि के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों में वृद्धि होती है।

पंचायत चुनाव में नजर आ रही महिला सशक्तिकरण की तस्वीर, मुख्यमंत्री ने दी बधाई

रंग लाई मुख्यमंत्री की अपील, प्रदेश में अब तक 570 पंचायतों में निर्विरोध बनें सरपंच

भोपाल। संवाददाता

मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में महिला सशक्तिकरण की तस्वीर नजर आ रही है। इस बार के पंचायत चुनावों में पुरुषों पर महिलाएं भारी हैं। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 570 सरंपच निर्विरोध निर्वाचित हो गए है। इनमें 380 महिलाएं और 190 पुरुष है। सागर की 79 वर्षीय बुजुर्ग रामरानी सबसे अधिक उम्र की सरपंच बनी हैं। भोपाल, सागर और नर्मदापुरम में तीन महिला सरपंच सिर्फ 21 वर्ष में निर्विरोध चुनी गई हैं।

शुक्रवार को नाम वापसी का अंतिम दिन था। इसके साथ ही कई जगह से चुनावी शोर और दांव-पेच के बगैर निर्विरोध चुनाव होने की सुखद खबर आई है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 48 जिलों में 570 सरपंच निर्विरोध चुने गए। इनमें 380 महिलाएं हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता से समरस पंचायत यानी निर्विरोध चुनाव की अपील की थी। इसके लिए सरकार की तरफ से पुरस्कार का ऐलान भी किया गया था। महिलाओं को चुनने पर पंचायत को 15 लाख रुपये देने की घोषणा की है। निर्विरोध चुनी जाने वाली ग्राम पंचायतों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सम्मानित करेंगे। प्रदेश में 22961 पंचायतें हैं। इसमें से अभी केवल 112 की ही सूची आई है। इसलिए इसलिए महिला सरपंचों की संख्या में इजाफा हो सकता है।

महाकौशल में सबसे ज्यादा निर्विरोध सरपंच: वहीं क्षेत्र के हिसाब से देखें तो महाकौशल से सबसे ज्यादा 45 और चंबल-ग्वालियर से सबसे कम 4 सरपंच निर्विरोध चुने गए हैं। इनके अलावा-मालवा से 25, नर्मदापुरम से 22, विंध्य से 9 और निमाड़ से 7 सरपंच निर्विरोध चुने गए हैं।

युवा सरपंच बने पहली पसंद

गांव की सरकार में युवा सरपंच उम्मीदवारों पर लोगों ने भरोसा जताया है। सबसे ज्यादा 40 निर्विरोध सरपंच 31 से 40 साल के उम्र के लोग बने हैं। इसमें 28 महिलाएं और 12 पुरुष शामिल हैं। 20 जिलों के आंकड़े भी यहीं कह रहे हैं। छिंदवाड़ा, बालाघाट, उमरिया, गुना, रीवा, सीहोर, विदिशा, झाबुआ, रतलाम और खरगोन में चुने गए सभी निर्विरोध सरपंच 50 साल से कम उम्र के हैं।

अजजा वर्ग के सरपंच भी आगे

कुल 112 ग्राम पंचायतों में सरपंच का चुनाव जातिगत समीकरण पर भी निर्भर रहा। इनमें से सबसे ज्यादा 65 सरपंच अनुसूचित जनजाति से और सबसे कम 6 सरपंच अनारक्षित वर्ग से चुने गए हैं। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग से 25 और अनुसूचित जाति से 16 सरपंच निर्विरोध चुने गए हैं।

हरदा में सबसे ज्यादा 35 सरपंच निर्विरोध

श्योपुर से 2, मुरैना से 6, भिंड से 7, ग्वालियर से 7, दतिया से 2, शिवपुरी से 16, गुना से 9, अशोक नगर से 9, सागर से 46, छतरपुर से 1, दमोह से 7, पन्ना से 6, सतना से 2, रीवा से 3, सीधी से 2, सिंगरौली से 2, शहडोल से 4, अनूपपुर से 1, उमरिया से 2, कटनी से 5, जबलपुर से 34, डिण्डोरी से 2, बालाघाट से 9, सिवनी से 34, नरसिंहपुर से 20, छिंदवाड़ा से 30, बैतूल से 4, हरदा से 35, नर्मदापुरम से 51, रायसेन से 37, विदिशा से 17, भोपाल से 1, सीहोर से 33, राजगढ़ से 3, आगर मालवा से 4, शाजापुर से 7, देवास से 19, खंडवा से 10, बुरहानपुर से 5, खरगोन से 5, बड़वानी से 4, अलीराजपुर से 5, झाबुआ से 2, धार से 20, इंदौर से 14, रतलाम से 12, मंदसौर से 5, नीमच से 8 निर्विरोध सरपंच निर्वाचित हुए है।

सागर में 79 वर्षीय सबसे बुजुर्ग निर्विरोध सरपंच बनीं

सागर जिले के रहली जपं की वाछलोन ग्राम पंचायत की अजा की 79 वर्षीय रामरानी सबसे बुजुर्ग सरपंच बनी हैं। केसली जपं की ग्रापं देवरी नाहरमऊ से अजा वर्ग की 21 वर्षीय जानकी गौंड निर्विरोध चुनी गई हैं। भोपाल की फंदा जपं की ग्राम पंचायत आदमपुर से अन्य पिछड़ा वर्ग की 21 वर्षीय महिला कृष्णा रावत भी निर्विरोध चुनी गई हैं। नर्मदापुरम जिले की बनखेड़ी जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत उमरधा से अनुसूचित जनजाति की 21 वर्षीय कुमारी जागृति सिंह जूदेव निर्विरोध चुनी गई हैं।

सीहोर जिले की 33 ग्राम पंचायतें समरस पंचायतें बनी

सीहोर जिले की 33 ग्राम पंचायतें समरस पंचायतें बनी हैं। विभिन्न जनपदों के सात वार्डों के प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। बुधनी जनपद की 9 ग्राम पंचायतें जिनके सरपंच निर्विरोध चुने गए, उनमें ग्राम पंचायत मढ़ावन, ग्राम पंचायत चिकली, ग्राम पंचायत जैत, ग्राम पंचायत वनेटा, ग्राम पंचायत खेरी सिलगेंना, ग्राम पंचायत कुसुमखेड़ा, ग्राम पंचायत पीलीकरार, ग्राम पंचायत ऊंचाखेड़ा तथा ग्राम पंचायत तालपुरा शामिल है। इसी प्रकार नसरुल्लागंज जनपद की 17 ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि निर्विरोध चुने गए हैं। इन ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत पिपलानी, इटावाकला, चौरसाखेडी, बडनगर, रिछाडिया कदीम, गिल्लौर, छापरी, हाथीघाट, खात्याखेडी, आंबाजदीद, तिलाडिया, सीलकंठ, ससली, कोसमी, मोगराखेड़ा लावापानी तथा बोरखेडी शामिल हैं। इछावर जनपद में ग्राम पंचायत मायोपानी, सहारन, गाजाखेड़ी तथा जमुनिया हटेसिंह एवं आष्टा जनपद में आवलीखेड़ा एवं अतरालिया तथा सीहोर जनपद में आमला ग्राम पंचायत के सरपंच निर्विरोध चुने गए हैं।

सात जनपद सदस्य निर्विरोध निर्वाचित: बुधनी जनपद के 6 वार्डों के जनपद सदस्य निर्विरोध चुने गए। इसमें खाण्डाबड, जहानपुर, बनेटा, सरदारनगर, बोरना, बकतरा वार्ड शामिल हैं। नसरुल्लागंज जनपद के वार्ड क्रमांक 5 इटारसी से भी निर्विरोध जनपद सदस्य निर्वाचित हुए।

सागर के मोकलपुर में सभी महिलाएं

सागर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत मोकलपुर में महिला सरकार बनी हैं। ग्रामीणों ने सर्वसहमति से सरपंच और 20 पंच महिलाओं को निर्विरोध चुना है।

मंदसौर में 4 ग्राम पंचायतों की कमान महिलाओं के पास

जिले में चार ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए गांव के प्रधान के रूप में महिलाओं को कमान मिली है। यह महिलाएं निर्विरोध रूप से सरपंच चुनी जाएगी। इन 4 गांव में सरपंच पद के लिए 1-1 नामांकन ही जमा हुआ है। इनमें मल्हारगढ़ विकासखंड की 85 ग्राम पंचायतों में अरनिया जटिया, आक्या बिका, सनावदा और भानपुरा विकासखंड की 44 ग्राम पंचायतों में लेदीकला में एक महिला शामिल है जो निर्विरोध रूप से सरपंच चुनी गई है।

हरदा प्रदेश में नंबर वन: जिले की 35 ग्राम पंचायतों में हुआ निर्विरोध निर्वाचन

किसान नेता एवं मध्यप्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का हरदा जिला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की समरस पंचायतें बनाने की पहल में अव्वल रहा है। यानी हरदा जिले को इस पहल के लिए नंबर वन कह सकते हैं। हरदा जिले में प्रदेश की सर्वाधिक 35 ग्राम पंचायतें निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं।हरदा जिले की यह सभी ग्राम पंचायतें अब विकास कार्यों को लेकर लखपति हो गई हैं।पंचायतों के लखपति होने पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने सभी को बधाई दी है।हरदा जिले के टिमरनी जनपद में ग्राम पंचायत, खिरकिया जनपद में 13 ग्राम पंचायत, हरदा जनपद में 16 ग्राम पंचायत निर्विरोध चुनी गईं।

निर्विरोध निर्वाचित पंचायतें

टिमरनी: आलमपुर, कुहीग्वाड़ी, उद्राकच्छ, खिड़कीवाला, रुंदलाए, गोदड़ी

खिरकिया: सोमगांव कलां, सारसूद, सांगवामाल, जिनवान्या, बावड़िया नवीन, महेंद्रगांव, बम्हनगांव, धनवाड़ा, बड़नगर, कल्याखेड़ी, खुदिया, मरदानपुर, बेड़यिाकला

हरदा: सामरधा, रहटाखुर्द, बूंदड़ा, जिजगांव खुर्द, धुरगाड़ा, बिछोलामॉल, रेलवां, भादुगांव, कोलिपुरा, नांदरा, खेड़ीनीमा, झाड़पा पं.(नवीन), केलनपुर, सुरजना, जामली दमामी नीलगढ़ दमामी शामिल हैं।

उमरिया के चौरी में निर्विरोध निर्वाचित हुए जनप्रतिनिधि, ग्रामीणों ने पेश की मिसाल

उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली के चौरा में ग्रामीणों ने निर्विरोध पंच सरपंच को चुन कर मिसाल पेश की है। ग्रामीणों ने बीते दिनों आपस में मिल बैठकर ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच और पंच मिल तय कर लिए। इस तरह से पंचायत का चुनाव बिना निर्वाचन के ही संपन्न हो गया। ग्राम पंचायत चौरी मे सरपंच पद पर द्वारिका प्रसाद सिंह, उप सरपंच पद पर बॉबी सिंह के अलावा पंच पद पर जितेंद्र सिंह, अलकेश सिंह, ललिता बाई, राजकुमार सिंह, किरण बाई, बेबी बाई, रोशन बाई, ज्ञान बाई, कृष्णपाल सिंह, रेशमी साहू निविरोध चुने गये हैं।

खंडवा जिले की बिलोरा बुजुर्ग ग्राम पंचायत पूरी परिषद निर्विरोध

जिले की बिलोरा बुजुर्ग ग्राम पंचायत और वहां के 19 पंच निर्विरोध चुने गए। सभी ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से प्रेम सिंह बघेल को सरपंच और 19 पंचों को अपने गांव के विकास के लिए निर्विरोध चुना।

नरसिंहपुर की बेलखेड़ी पिंक पंचायत बनी, निर्विरोध चुनी गईं पंच और सरपंच नरसिंहपुर जिले में पहली बार अस्तित्व में आई नवीन ग्राम पंचायत बेलखेड़ी ने मिसाल पेश की है। तीन गांवों ग्राम बेलखेड़ी, जैथारी, सलैया को मिलाकर बनाई गई इस नई पंचायत में सभी पंच और सरपंच आपसी सहमति से निर्विरोध चुने गए हैं। खास बात यह है कि चुनी गईं सभी पंच और सरपंच महिलाएं हैं।

समरस पंचायतें होंगी पुरस्कृत

ऐसी ग्राम पंचायत जिसके सरपंच निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं उन पंचायतों को पुरस्कार राशि रुपये 5 लाख तथा सरपंच पद हेतु वर्तमान निर्वाचन एवं पिछला निर्वाचन निरंतर निर्विरोध होने पर पुरस्कार राशि रूपये 7 लाख एवं ऐसी ग्राम पंचायत जिसके सरपंच तथा सभी पंच निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। उन पंचायतों को पुरस्कार राशि रुपये 7 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा। ऐसी ग्राम पंचायत जिसके सरपंच तथा सभी पंच महिला निर्वाचित हुए हैं, पुरस्कार राशि रुपये 12 लाख एवं पंचायत में सरपंच एवं पंच के सभी पदों पर महिलाओं का निर्वाचन निर्विरोध रूप से हुए हैं उन्हें राशि 15 लाख पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

मोदी ने साकार किया एक भारत-संपूर्ण भारत का सपना, 60 पर भारी 8 साल

लोकतंत्र का मनोरथ आम लोगों की भलाई होता है। हमारे देश में लोकतंत्र तो स्थापित हुआ किंतु शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, सामाजिक न्याय, सड़क जैसे सामाजिक सरोकार से जुड़े जन-कल्याणकारी मुद्दे सरकार की प्राथमिकताओं में वर्ष 2014 में शामिल किए गए। 26 मई 2014 का दिन देश के भविष्य का ऐतिहासिक और प्रभावकारी दिन बन गया, जब देश का नेतृत्व जमीन से जुड़े उस महान नेता को मिला, जिनकी हर साँस में भारत माता की बेहतरी की अनगिनत कोशिशें और कार्यों में देश के प्रति असीम प्रतिबद्धता रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समूचे देश को एक सूत्र में बांध कर एक भारत-सम्पूर्ण भारत के सपने को साकार कर दिया है।

दरअसल जन-कल्याण की सबसे आवश्यक मांग होती है, ऐसा सकारात्मक और दूरदर्शी नेतृत्व जिनमें आम जनता के सर्वांगीण विकास करने की जिजीविषा और कार्य-योजना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समूचे देश को एक सूत्र में बांध कर एक भारत-सम्पूर्ण भारत के सपने को साकार कर दिया है। आजाद भारत में विकास के सपने तो कई सरकारों ने दिखाए, लेकिन उनके प्रशस्त होने का सिलसिला शुरू हुआ वर्ष 2014 से। विकास का अर्थ हमेशा सकारात्मक बदलाव से होता है और यह बदलाव अब नजर आ रहा है लोगों के मनोभावों में, युवाओं के सपनों में, बुजुर्गों के विश्वास में, मातृ-शक्ति के सशक्तिकरण में, उद्यमिता में और सरहदों की रक्षा करने वाले हमारे जांबाज जवानों में।

370 खत्म कर पुरानी घाव को भरा: वर्ष 1962 में चीन से युद्ध में हमारे जवानों के पास न तो उपयुक्त हथियार थे और न ही पूर्वोत्तर की जटिल परिस्थितियों तक पहुँचने के मार्ग। नतीजा हमारे जवानों को रसद तक न मिल पाई। आज का भारत बदल गया है। कश्मीर से धारा 370 खत्म कर उस घाव को भर दिया गया है, जिससे भारत का हर नागरिक बैचेन रहता था। मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक के उस दंश से मुक्ति मिल गई है, जिससे कई माता-बहनों की जिन्दगी तबाह हो जाती थी। देश की सुरक्षा प्रधानमंत्री मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है और सेना का वन रैंक-वन पेंशन का सपना साकार कर दिया गया है। चीन से सीमा विवाद के चलते और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों से जूझते भारत ने अब अपनी सामरिक स्थिति को मजबूत कर लिया है। पूर्वोत्तर के प्रवेश द्वार असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच अब बोगीबिल पुल के बनने से सेना देश के किसी भी हिस्से से बहुत कम समय में चीन से लगती सीमा पर पहुँच जाएगी। सेना की लामबंदी और फ़ॉरवर्ड क्षेत्र में रक्षा आपूर्ति का काम आसान हो जाएगा। इस प्रकार चीन पर अब भारत को सामरिक बढ़त हासिल हो गई है।

विकास के लिए किए क्रातिकारी परिवर्तन: विकास का अर्थ है कि सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना, संस्थाओं और सेवाओं की बढ़ती क्षमता जो संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से कर सकें, जिससे जीवन स्तर में अनुकूल परिवर्तन आए। देश में कच्ची सड़कों को पक्की सड़कों में बदल दिया गया है। देश की बड़ी आबादी के पास रहने के लिए घर नहीं थे,आजादी के बाद अब जाकर उन्हें पक्का घर नसीब हुआ है। एक दौर था भारत की कन्या भ्रूण हत्या को लेकर वैश्विक बदनामी होती थी। अब बेटी बचाओ-बेटी-पढ़ाओ अभियान को वैश्विक स्तर पर सराहा जा रहा है। उज्जवला योजना बहु-बेटियों के लिए वरदान बन गई है।

कमल पटेल
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री
मध्य प्रदेश सरकार

गरीबों की पहुंच बैकों तक हुई: इसी प्रकार बैंक में खाता खुलवाना और एटीएम रखना अमीरों तक सीमित था। आजादी के 6 दशक बाद भी भारत में बड़ी संख्या में ऐसी आबादी थी, जिन्हें बैंकिंग सेवाएं हासिल नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बुनियादी समस्या का समाधान करने के लिए जन-धन योजना की शुरुआत की। इस योजना ने लाखों भारतीयों के जीवन और भविष्य को पूरी तरह से बदल दिया है। अब देश की अधिकांश आबादी के पास उनका बैंक अकाउंट है और इससे सरकार की सीधी मदद उनके बैंक अकाउंट तक पहुंचती है।

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना: देश की आबादी की तकरीबन 68 फीसदी जनसंख्या गांवों में रहती है। गाँवों को विकास से जोड़ कर ही देश का चहुंमुखी विकास हो सकता है। प्रधानमंत्री ने किसानों और ग्रामीणजन के जीवन में बदलाव की एक स्वर्णिम योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से भारत के ग्रामीण समाज का विकास और प्रगति से सीधे जुडने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इससे किसानों और ग्रामीणों की भूमि को लेकर जो नया विजन सामने लाया गया है, वह विकास के नित नए आयाम स्थापित कर रहा है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि: देश के अन्नदाता किसानों का आत्मबल मजबूत करने और खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए भी विशेष प्रयास हुए हैं। प्रधानमंत्री की विशेष पहल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बनाई गई, जिसमें लघु एवं सीमान्त किसानों को एक साल में तीन किश्तों में 6 हजार रूपये दिये जा रहे हैं। हाल ही में देश के 10 करोड़ से अधिक किसानों को सम्मान निधि की 11वीं किश्त जारी की गई। किसानों को प्राकृतिक खेती से भी जोड़ा जा रहा है।

स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत : देश का नेतृत्व संभालते ही प्रधानमंत्री मोदी ने दो बड़ी योजनाओं, मेक इन इंडिया और स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। पहली योजना का मक़सद उद्योग और निवेश को बढ़ावा देना और दूसरी का स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करना था। मेक इन इंडिया का मक़सद लालफीताशाही को कम करना, विदेशी उद्योगों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना और देश की जन-शक्ति को रोज़गार प्रदान करने की अनुमति देने का था। सरकार ने आगे बढ़ते हुए विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के द्वार भी खोल दिए। स्वच्छ भारत अभियान ने दुनिया में देश की छवि को बदल दिया है। यह अभियान जन-आंदोलन बन गया है।

नमामि गंगे: नमामि गंगे से देश की 40 फीसदी आबादी के जीवन पर आमूल-चूल परिवर्तन आया है। वहीं भारत के हर गाँव तक बिजली पहुँचाने के महत्वाकांक्षी मिशन ने देश को रौशन कर दिया है। देश जन धन-आधार और मोबाइल के उपयोग से आमूल-चूल बदलाव करने वाले सुधारों की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये प्रत्यक्ष नकद हस्तांकरण के लिए एक यूनीक कॉम्बिनेशन है। इससे अनोखी पद्धति से बिना किसी लीकेज के लोगों तक सीधे लाभ पहुँचाए जा सकेंगे। शिक्षा की गुणवत्ता और उसकी पहुँच बढ़ाने के लिए कई यूनिक उपाय किए गए हैं। बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दिया जा रहा है। चाहें ये रेलवे हो, सड़क हो या शिपिंग। सरकार संपर्क बढ़ाने के लिए बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर फोकस कर रही है। सागरमाला परियोजना की तरह तटीय समुदायों के विकास के जरिए एक समग्र बंदरगाह आधारित विकास सुनिश्चित किया गया है।

50 साल बाद बंजर हो जाएंगे हमारे खेतः जग्गी वासुदेव

मिट्टी की सेहत को लेकर अब सवाल खड़े होने लगे है। एक्सपर्ट पहले से चेताते रहे थे लेकिन ईशा फाउंडेशन के संस्थापक जग्गी वासुदेव ने सेव सॉयल मूवमेंट के तहत दुनिया भर के देशों तक ये बात पहुंचाई तो आम लोग भी इस बारे में बात करने लगे हैं। सदगुरु ने मिट्टी बचाओ अभियान के तहत 24 देशों में यात्रा करके लोगों को ये समझाने का प्रयास किया कि मिट्टी को जीवन के इस चक्र का हिस्सा बनाएं वर्ना आने वाली पीढ़ियों को हमारी कमियों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वो कहते हैं कि पूरे विश्व का पिछले 25 सालों में उपजाऊ जमीन का 10 प्रतिशत हिस्सा बंजर हुआ है। ऐसे ही रहा तो 40 से 50 सालों के बाद हमारे पास खेती के लिए जमीन न के बराबर होगी। भारत में कृषि एक मात्र साधन है जो सदियों से चलता आ रहा है, कृषि के क्षेत्र में ज्यादा फ़सल कम लागत का फार्मूला, जल्द से जल्द फसल बदलना, रासायनिक खाद का हद से ज्यादा इस्तेमाल मिट्टी को अंदर ही अंदर कमजोर करता चला गया। दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट के संयुक्त निदेशक अनुसंधान इन्द्र मणि कहते हैं कि हरित क्रांति के दौर में किसानों को अधिक पैदावार के लिए प्रोत्साहित किया गया लेकिन मिट्टी के भौतिक, रासायनिक, जैविक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया गया। वो जिस रासायनिक खाद का अधिक से अधिक उपयोग कर रहे थे, वो मिट्टी के समग्र स्वास्थ्य में कमी ला रही थी।

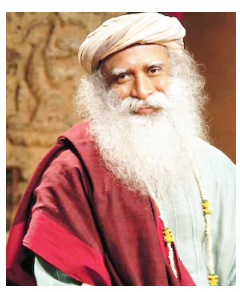

मौसम ने भी बनाया मिट्टी को मरुस्थली: देश में पिछले कुछ सालों में क्लाइमेट चेंज या फिर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम के व्यवहार में कई फेर बदल देखने को मिले, कहीं बाढ़, तो कहीं सूखा। ये ऐसे हालात रहे जिसने मिट्टी की नमी को या तो खत्म कर दिया या उसके पोषक तत्व को खत्म कर दिया। साल दर साल एक इलाके में इस तरह के व्यवहार से मिट्टी की गुणवक्ता खत्म होती चली गई।

मौसम विभाग में कृषि विभाग के निदेशक के.के. सिंह बताते हैं कि ये शायद प्रकृति का ये एक खेल है जिसको हमको समझना होगा। मौसम बदलना क्लाइमेट चेंज का एक उदाहरण है और इसको रोकना है तो पूरे विश्व को सोचना होगा, बात कृषि की हो तो अब भी भारत में 79 प्रतिशत किसान बारिश पर निर्भर होकर खेती करते हैं, ऐसे में बदलते मौसम का सबसे ज्यादा असर खेती पर ही पड़ा है।

मिट्टी से गायब हो रहे पोषक तत्व: आज के दौर में हर किसान कोशिश करता है कि खेत की एक गज जमीन को भी खेती में प्रयोग कर ले। रासायनिक खाद, कीटनाशकों का इस्तेमाल खेतिहर जमीन में मौजूद पोषक तत्वों को (जिनसे उपजाऊ क्षमता तय होती है) खत्म कर देती है और धीरे धीरे वो जमीन बंजर होनी शुरू हो जाती है।

कहां गलती कर रहे हैं किसान: फ़सल चक्र अपनाना न अपनाना, गोबर, हरी खाद, वर्मी कम्पोस्ट, नाडेप कम्पोस्ट का इस्तेमाल नहीं करना, मृदा परीक्षण कराए बिना अंधाधुंध उर्वरकों का इस्तेमाल ,मिट्टी से आर्गेनिक मैटर का घटना, अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों की बुवाई करना, लगातार नहरों/लवणीय जल से सिंचाई करने के कारण खेतों से सूक्ष्म पोषक तत्व कम हो रहे हैं। रोटावेटर/कल्टीवेटर से ज्यादा गहरी जुताई करने से जिंक, सल्फ़र, आर्गेनिक मेटर और नाइट्रोजन की कमी होने लगती है। खेतों की मेड़बंदी न किए जाने से भी पोषक तत्व पानी के साथ बहकर निकल जाते हैं।

समय-समय पर मिट्टी की जांच जरूरी

हिमाचल प्रदेश के डायरेक्टर एग्रीकल्चर एन के धीमान बताते हैं पिछले कुछ समय से हमने किसानों को ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रेरित किया है और किसान अब उसको अपना रहे हैं पर असल में किसानों को ये समझना होगा की ये जमीन ये मिट्टी उनको अपनी अगली पीढ़ी को देकर जानी है, अब वो उपजाऊ जमीन देना चाहते हैं या बंजर उसके लिए उनको सोचना होगा। हमारी टीम मिट्टी की जांच समय समय खेतों से सैंपल लेकर करती जाती है और कमी होने पर हम उस मिट्टी में पोषक तत्वों को पूर्ति भी करते है पर बंजर होती जमीन के दो मुख्य कारण है एक तो किसी उपजाऊ भूमि को खेती के लिए प्रयोग नहीं करना या किसी उपजाऊ भूमि पर हद से ज्यादा रसायनों का प्रयोग करना। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मिट्टी की गुणवत्ता में कमी जहां सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है उसमे पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। इनमें से अधिकांश राज्यों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी व्यापक है। अगर ऐसे ही हालात रहे हैं तो 2045 तक हमारी 40 प्रतिशत उत्पादन क्षमता में कमी आएगी।

कहते हैं वक्त रहते सुधार ही भविष्य को बेहतर करने का प्रयास होता है किसान अपनी भूमि को मां की तरह पूजते हैं, इसलिए उनको जरा सा जागरूक करने से मिट्टी की गुणवक्ता में वृद्धि होगी और इससे भविष्य में दिखने वाली एक बड़ी विश्वव्यापी समस्या से निजात भी मिलेगा, इसके लिए हमें आज ही सोचना होगा। ये कबीर दास का ये दोहा बताता है कि समय रहते नहीं सचेत हुए तो देर हो जाएगी।

माटी कहे कुम्हार से तु क्यों रोंधे मोए
एक दिन ऐसा आएगा मैं रोधुगी तोए

संतुलित जीवन के महत्वपूर्ण स्तंभ पर्यावरण, पशु-पक्षी, एवं मनुष्य

जीवित पशु पक्षी, जैवविविधता को जन्म देकर पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते हैं। खाद्य श्रृंखला को बरकरार रखने के लिए, पर्यावरण संतुलन के लिए हानिकारक जीव-संख्या का नियंत्रण, पर्यावरण की साफ-सफाई एवं अप्रत्यक्ष रूप से वृक्षारोपण आदि में इनकी महत्वता होती है। पशुधन और कुक्कुट के उत्पादन जो कि एक तरफ मनुष्य जीवन के लिए काफी ज्यादा जरूरी होते हैं, वही जल वायु एवं मृदा को प्रभावित करने वाले कारकों द्वारा पर्यावरण पर महत्वपूर्ण रूप से असर डालते हैं। खाद या पशु अपशिष्ट विशेष रूप से गहन पशु कृषि के साथ चिंता का प्रमुख स्रोत होते हैं, लेकिन ये तथ्य बिल्कुल रूचि लेने योग्य है कि यह खाद एवं पशु अपशिष्ट पदार्थ कृषि में युरिया, पोटास, डीडीटी जैसे विषैले पदार्थों का प्रतिस्थापन तय करते हैं एवं जैविक कृषि द्वारा अधिक उपज पैदा करने में कारगर होते हैं। देखा जाता है कि अन्य स्थानों की तुलना में मृत जीवों के निकट, वनस्पतियों में पांच गुना अधिक वृद्धि होती है, मरणोपरान्त परजीवियों एवं शाकाहारी कीड़ों और उनके शिकारियों की संख्या में भी चार गुना वृद्धि होती है। यह कहावत जीवित हाथी लाख का और मरा सवा लाख का बिल्कुल अपने चरित्रार्थ को प्रतीत करता है, जोकि अनेक शाकाहारी जीवों और उनके शिकारियों के लिए महत्वपूर्ण आहार होता है। वहां की मिटटी पोषक तत्वों से भरपूर होती है। पर्यावरण मनुष्य एवं पशु जीवन के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए हमें एकल स्वास्थ के दृष्टिकोण पर ज्यादा जोर देना चाहिए। पर्यावरण नीतियों एवं विकास कार्यक्रमों के बीच समन्वय की संकल्पना अतिआवश्यक है। इसके तहत पर्यावरण, पशु तथा मानव स्वास्थ्य के अंतर्संबंधों को प्रत्येक स्तर पर शामिल कर उनका सर्वेक्षण किया जाता है एवं पशु तथा मानव स्वास्थ्य परिस्थितिकी तंत्र से उत्पन्न खतरों को संबोधित करने के लिये बहु आयामी उपाय होते हैं। रुडोल्फ विर्को जो वर्ष 1856 में आधुनिक पैथोलॉजी के जनक के रूप में विख्यात थे, उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा में कोई स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं है। बढ़ती मानव आबादी के कारण, नए भौगोलिक क्षेत्रों में मानव विस्तार पर्यावरण संबंधी व्यवधान, अंतरराष्ट्रीय यात्रा और व्यापार एवं मनुष्यों का वन्य जीवों के संपर्क में आना यह सभी घटक, पर्यावरण मनुष्य एवं पशु जीवन को मुख्यता प्रभावित करते हैं । ऐसा माना जाता है कि मनुष्य को प्रभावित करने वाले संक्रामक एवं जूनोटिक रोगों में से 65फीसदी से अधिक जूनोटिक रोगों की उत्पत्ति के मुख्य स्रोत पशु एवं वातावरण में बदलाव होता है। इसके अतिरिक्त विषाणु एवं जीवाणुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इन्हीं कारणों से उत्पन्न होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार, वन्यजीवों में लगभग 1.7 मिलियन से अधिक विषाणु पाए जाते हैं, जिनमें से अधिकतर के जूनोटिक होने की संभावना है। इसका तात्पर्य है कि समय रहते अगर इन विषाणुओं का पता नहीं चलता है, तो भारत को आने वाले समय में कोविड-19, निपाह वायरस, मंकीपॉक्स, एवियन इनफ्लुएंजा एवं स्वाइन फ्लू जैसी कई महामारियों का भयंकर सामना करना पड़ सकता है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए कृषि वैज्ञान, मनुष्य एवं पशु चिकित्सा संस्थानों के मध्य सूचनाओं के आदान-प्रदान को सुचारू रूप से व्यवस्थित करना चाहिए।। इसे देखते हुए भारत को समग्र सहयोग के साथ एकल स्वास्थ्य सिद्धांत के प्रति जागरूकता फैलानी चाहिये तथा इस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास हेतु निवेश की विशेष आवश्यकता है। मौजूदा पशु स्वास्थ्य और रोग निगरानी प्रणाली, जैसे-पशु उत्पादकता और स्वास्थ्य के लिये सूचना नेटवर्क एवं राष्ट्रीय पशु रोग रिपोर्टिंग प्रणाली को समेकित करने की आवश्यकता है। अनौपचारिक बाज़ार और स्लॉटरहाउस ऑपरेशन (जैसे, निरीक्षण, रोग प्रसार आकलन) के लिये सर्वोत्तम दिशा-निर्देशों का विकास करना और ग्रामीण स्तर पर प्रत्येक चरण में वन हेल्थ के संचालन के लिये संस्थागत तंत्र की स्थापना करना चाहिए।

डॉ सलिल कुमार पाठक,
डॉ अमिता तिवारी, डॉ देवेन्द्र कुमार गुप्ता, डॉ कविता राय
पशु औषधि विभाग, पशु चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर

लक्ष्य को पूरा करने तेजी से चल रहा काम, मानसून की आमद ने बढ़ाई ग्रामीण विकास विभाग की चिंता

प्रदेश में बन रहे 5 हजार 638 अमृत सरोवर, साबित होंगे वरदान

भोपाल। संवाददाता

मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर योजना पर तेजी से काम चल रहा है। 52 जिलों में योजना के तहत केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी अमृत सरोवर योजना मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में जल संरक्षण की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि होगी। क्रियान्वयन के लिए योजना पर तेजी से काम चल रहा है। मध्य प्रदेश में लगभग 5 हजार 638 बड़े तालाब विकसित किए जा रहे हैं। प्रत्येक जिले में 100 तालाब विकसित करने का लक्ष्य है। उम्मीद है भविष्य में ग्रामीण इलाकों के लिए वरदान साबित होंगे।

मानसून की आदम के साथ ही ग्रामीण विकास विभाग की चिंता बढ़ गई है। क्योंकि इसके कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई अमृत सरोवर योजना के लिये निर्धारित 3000 संरचनाओं को पूरा करने का लक्ष्य पिछड़ सकता है। जबकि केंद्र सरकार की इस योजना के तहत प्रदेश भर की 5 हजार 638 जल संरचनाओं को सुदृढ़ करने के लिये मार्च 2023 तक का लक्ष्य रखा गया है। लिहाजा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत संचालित इस लोक महत्व की योजना को तय समय पर पूरा करने के लिये विभाग को माह में औसतन 794 सरोवरों का निर्माण किसी चुनौती से कम नहीं है।

वजह यह भी है कि लगभग 700 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से तैयार होने वाले 5 हजार 638 अमृत सरोवरों में से 5 हजार 449 पर निर्माण कार्य शुरू हो पाया है। बावजूद इसके 4 हजार 82 अमृत सरोवरों का निर्माण कार्य 25 प्रतिशत तक ही हो सका है। विभागीय अधिकारियों की माने तो यह कार्य बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है। यही वजह है कि 134 सरोवरों का 50 प्रतिशत से अधिक और 1204 का 25 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण कर लिया गया है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि इनमें 29 अमृत सरोवरों के निर्माण का कार्य 75 प्रतिशत तक हो गया है। क्योंकि विभागीय अधिकारियों ने 15 जून तक 3000 संरचनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा था। क्योंकि तब अनुमान था कि मानसून अपनी आमद -5-6 जून के आसपास देगा। लेकिन इसके 10 दिन पहले ही दस्तक दे देने के कारण तय लक्ष्य पर विपरीत असर पड़ सकता है।

वृहद उद्देश्य को पूरा करेंगे अमृत सरोवर

जल संरक्षण के लिए प्रदेशव्यापी अभियान के तहत निर्मित यह सरोवर वृहद उद्देश्य को पूरा करेंगे। इसके तहत जहां इनका उपयोग सिंचाई, मत्स्य-पालन, सिंघाड़ा उत्पादन आदि प्रयोजन में किया जायेगा। वहीं अपने सौंदर्यीकरण और पौधरोपण के कारण यह भविष्य में सैर-विहार के रूप में लोगों के पसंदीदा स्थलों में सुमार होंगे। क्योंकि ग्राम पंचायत तालाब के किनारे फलदार और औषधीय पौधों को रोपेगी।

सरोवर प्राधिकरण पर होगा निगरानी का जिम्मा

अमृत सरोवर की निगरानी का जिम्मा सरोवर प्राधिकरण पर होगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मातहत काम करेगा। भविष्य में इसकी निगरानी में ही प्रदेश में नए तालाब बनने से लेकर इनकी मरम्मत के सारे काम होंगे। लिहाजा, विभाग में सरोवर प्राधिकरण के नए सेटअप की तैयारी शुरू हो गई है। मंत्री परिषद की मंजूरी के बाद इस पर अमल शुरू हो जाएगा।

प्रत्येक जिले में लगभग 4 करोड़ रुपए खर्च कर रही है सरकार

तालाब का निर्माण करने में सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। एक अनुमान के मुताबिक प्रत्येक तालाब पर लगभग 4 लाख रुपए की राशि खर्च की जा रही है। राशि का निर्धारण स्थान और परिस्थिति अनुसार कम ज्यादा हो सकता है। इस तरह तालाब के विकास में लगभग 4 करोड़ की राशि का बजट है। उज्जैन में राशि दोगुनी अर्थात 8 करोड़ रुपए के आसपास है।

जन भागीदारी से जुटाएंगे राशि

केंद्र सरकार की अमृत सरोवर योजना से प्रत्येक जिले में 100 तालाब बनाए जा रहे हैं। इसके लिए प्रत्येक जिले में लगभग चार करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। इस हिसाब से एक तालाब पर करीब 4 लाख रूपये खचज होंगे। योजना के विस्तार तथा उद्देश्य के मद्देनजर राशि को बहुत कम माना गया है। इसको देखते हुए बताया जा रहा है कि गांवों में जनभागीदारी से भी राशि एकत्र इस योजना को मूतज रूप दिया जाएगा।

हम 15 जून तक करीब 3000 अमृत सरोवरों का निमाज्ण कायज पूरा करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। यदि समय पूर्व मानसून आता है और तेज बारिश होती है तो हम मान सकते हैं कि इस कायज की सीमा अगस्त तक बढ़ जाएगी।
सूफिया फारूखी, आयुक्त मनरेगा

मध्य प्रदेश, आन्ध्रप्रदेश बने अन्य राज्यों के लिए मॉडल

कृषि अवसंरचना कोष योजना में मप्र नंबर 1

नई दिल्ली, मध्य प्रदेश अभी तक पूरे देश से प्राप्त आवेदन पत्रों में 38 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ सर्वश्रेष्ठ बना हुआ है और उसी के अनुपात में 30 प्रतिशत पूरे बजटीय आवंटन का हिस्सा उसे मिला है। जो कि योजना की मध्य प्रदेश में अभूतपूर्व सफलता की कहानी कहता है।

भारतीय कृषि में एक नये अध्याय की शुरूआत हो चुकी है। जहां एक ओर भारतीय कृषि, डिजीटलाईजेशन की तरफ आगे बढ़ी है वहीं दूसरी ओर पीएम किसान योजना, कृषि अवसंरचना कोष योजना और किसान उत्पादक संगठन, स्टार्टअप, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आदि के क्रियान्वयन से भारतीय कृषि को एक नई ऊंचाई मिली है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान को सरकार स्वीकार करती है और उसके विकास की यात्रा को तेज करने के लिए कृतसंकल्पित है। इसी का परिणाम है कि विगत 8 वर्षों में खाद्यान्न व बागवानी फसलों के उत्पादन में हम विश्व में श्रेष्ठ रहे हैं। सरकार लगातार नई-नई योजनाओं को बनाने और उनके बेहतर क्रियान्वयन के प्रति ईमानदार रही, परिणामस्वरूप लगातार खाद्यान्न उत्पादन बढ़ता गया है। बजटीय आवंटन का लगातार बढना भी सरकार की नेक नीयत

और ईमानदार सोच का परिणाम है। सरकार ने मंत्रालय के प्रयास से जिन नई योजनाओं को किसानों को समर्पित किया है, उन योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य सरकारों की भूमिका को भी याद रखा जायेगा। किसी भी योजना की सफलता उस योजना की क्रियान्वयन, निगरानी, समीक्षा, मूल्यांकन और आ रही चुनौतियों के समाधान के बाद ही होती है। इन सभी बिन्दुओं पर मंत्रालय एवं सरकार ने विगत 8 वर्षों में विशेष ध्यान दिया है। कृषि विकास और उत्पादन की गतिशीलता को अगले चरण तक ले जाने के लिए बुनियादी ढांचे की आवश्यकता को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने अनुभव किया और सरकार से अपनी मंशा बताते हुए कृषि अवसंरचना कोष योजना की रूपरेखा रखी जिसे सरकार ने किसान हितैषी, सकारात्मक पहल और ईमानदार सोच के साथ अपनी मंजूरी दी।

12504 स्वीकृत परियोजनाओं में होगा लगभग 15599 करोड़ निवेश

आंकड़े बताते हैं कि अभी तक कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत 21600 आवेदन पत्र पोर्टल पर उपलब्ध हैं। 20 मई, 2022 तक करीब 12504 परियोजनायें स्वीकृत हो चुकी हैं और इन योजनाओं में लगभग 15599 करोड़ रूपये निवेश होगा। इसके लिए 9129 करोड़ रूपये स्वीकृत हो चुके हैं और इस योजना के अंतर्गत 4890 करोड़ रूपये जारी भी किये जा चुके हैं। सूत्र बताते हैं कि स्वीकृत की गई राशि में सहकारी बैंकों द्वारा 33.7 प्रतिशत और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 66.3 प्रतिशत राशि की स्वीकृति दी जा चुकी है। अगर राज्यवार इस योजना के तहत स्वीकृति राशि की बात करें तो ग्राफबताते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पूरी स्वीकृत राशि का तीस प्रतिशत भाग स्वीकृत किया गया, वहीं आंध्र प्रदेश सरकार 19 प्रतिशत की भागीदारी के साथ द्वितीय स्थान पर है। इन प्रदेशों में इस योजना के सफल क्रियान्वयन का यह उदाहरण है। यह बात चौंकाती है कि देश में 11763 सत्यापित वाणिज्यिक बैंकों के आवेदनों में 58 प्रतिशत आवेदन पत्र मात्र मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान से हैं। राज्यवार अवसंरचना निर्माण के रूझान मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश को सभी राज्यों से आगे बनाये हुए हैं जो योजना की प्रगति का परिचायक है। मध्य प्रदेश को अब तक 1488 करोड़ रूपये आवंटित

पूरे देश से प्राप्त आवेदन पत्रों में 38 प्रतिशत हिस्सेदारी मध्य प्रदेश की

मध्य प्रदेश अभी तक पूरे देश से प्राप्त आवेदन पत्रों में 38 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ सर्वश्रेष्ठ बना हुआ है और उसी के अनुपात में 30 प्रतिशत पूरे बजटीय आवंटन का हिस्सा उसे मिला है। जो कि योजना की मध्य प्रदेश में अभूतपूर्व सफलता की कहानी कहता है। आंध्र प्रदेश की सफलता की कहानी बताते हुए मुझे पहले यह बताना है कि यहां पर प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों से 1367 आवेदन पत्र के लिए 1519 करोड़ स्वीकृत हुए जिससे राज्य के किसानों की आय बढ़ाने के लिए फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में इस योजना के क्रियान्वयन में आ रही चुनौतियों के लिए राज्य सरकार का सहयोग सराहनीय रहा और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के पास पर्याप्त मार्जिन मनी न होने पर राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराना प्रशंसनीय कार्य रहा है। कृषि अवसंरचना विकास के लिए भूमि की व्यवस्था सरकार द्वारा किया जाना वांछित था। योजना की सफलता के लिए राज्य सरकार का सहयोग अन्य राज्यों के लिए उदाहरण है। आंध्र प्रदेश राज्य के किसानों को संकटकालीन बिक्री से बचाने और प्रत्येक किसानों लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए भंडारण व्यवस्था उपलब्ध कराकर ई-मार्केटिंग प्लेटफार्म द्वारा देशभर के व्यापारियों से जोड़ा गया।

पशुजन्य संक्रमण, जो संक्रमित जानवरों से इंसानों में फैल सकता है

अश्व प्रजाति के पशुओं में ग्लैंडर्स

अश्व प्रजाति के पशुओं में ग्लैंडर्स नाम की बीमारी पायी जाती है। ग्लैंडर्स यह एक जीवाणु जनित रोग है। बर्कहोल्डेरिया मैलियाई नामक जीवाणु से अश्व प्रजाति के पशुओं में ग्लैंडर्स बीमारी होती है। ग्लैंडर्स यह रोग प्रमुख रूप से घोड़ों को प्रभावित करता हैं, हालांकि गधे और खच्चरों को भी यह बर्कहोल्डेरिया मैलियाई जीवाणु संक्रमित कर सकता है। यह एक पशुजन्य संक्रमण है और संक्रमित जानवरों से इंसानों में फैल सकता है। बर्कहोल्डेरिया मैलियाई जीवाणु से संक्रमित चारे और पानी से यह बीमारी अन्य घोड़ों में या गधे और खच्चरों मे फैलती है। इस रोग में त्वचा पर घाव या फोड़ा हो जाता है साथ ही यह फोड़े ग्लैंडर्स प्रभावित अश्व की पैरों पर भी पाएं जाते है। ग्लैंडर्स प्रभावित अश्वों के ऊपरी श्वसन तंत्र और फेफड़ों में भी फोड़े या घाव हो जाते हैं। नाक से और त्वचा पर हुए फोड़ों से निकलने वाले संक्रमित बहाव से जीवाणु बर्कहोल्डेरिया मैलियाई दूसरे जानवरों को ग्लैंडर्स बीमारी फैलाकर नुकसान पहुँचा सकता है। ग्लैंडर्स यह बीमारी मध्य प्रदेश से सटे हुए प्रदेशों मे जैसे की उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों मे घोड़ों में पायी जाती है । तथा भारत के अन्य प्रदेशों मे भी घोड़ों में यह बीमारी पायी गयी है। अन्य घोड़ों के अलावा सफेद रंग के घोड़ों की पर्व या त्योहारों मे सामान्यत: मांग रहती है। और ऐसे घोड़ो को दूर प्रदेशों से, मध्य प्रदेश मे लाया जाता है। अत: घोड़ो को जब दूसरे प्रदेशों से खरीदकर मप्र लाया जाता है तब उन घोड़ो में यह बीमारी न हो इसकी जाँच-पड़ताल अवश्य कर लेनी चाहिए।

आपका जानवर अगर नैदानिक जांच में संक्रमित पाया जाता है तो उसे नष्ट करना ही उचित होता है। घोड़े के विनिष्टीकरण के लिए भारत सरकार क्षतिपूर्ति शुल्क वहन करती है।'संक्रामक और संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण' के तत्वाधान में पशु अधिनियम द्वारा 25,000 रुपये तक की क्षतिपूर्ति सम्बंधित व्यक्ति को दी जाती है। बर्कहोल्डेरिया मैलियाई नामक जीवाणु की मानवों में संक्रामकता के कारण, भारत में ग्लैंडर्स और फार्सी अधिनियम 1899 को अधिनियमित किया गया था । मध्य प्रदेश राज्य में ग्लैंडर्स के मानवीय मामले न के बराबर है। ग्लैंडर्स के संदिग्ध मामलों को सम्बंधित अधिकारियों को बताना अतिआवश्यक है। ग्लैंडर्स रोग से प्रभावित जानवरों की जांच करने और पुष्टि करने के बाद सकारात्मक जानवरों को नष्ट किया जाता है तथा बीमारी को मनुष्यों और जानवरों में फैलने से बचाने के लिए इन जानवरों को दफना दिया जाता है । राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र भारत मे हरियाणा राज्य के हिसार मे स्थित है। यहाँ पर घोड़ों के विभिन्न बीमारियों की जांच-निदान और टीका विकसित किया जाता है। आप अपने घोड़े या अन्य जानवरों में (जैसे की गधे व खच्चर) इस रोग के संकेत और लक्षण देखते हैं, तो कृपया अपने आस-पास के पशु चिकित्सा सुविधा केंद्र से संपर्क करें।

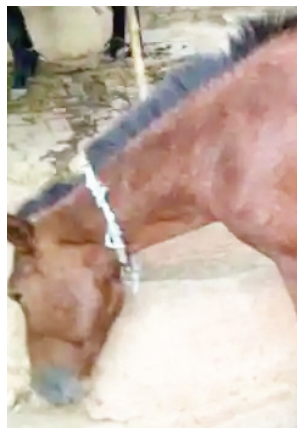

डॉ. स. दि. औदार्य (सहायक प्राध्यापक), डॉ. नी. श्रीवास्तव (सहयोगी प्राध्यापक) और डॉ. अं. कि. निरंजन (सहायक प्राध्यापक), पशुचिकित्सा सुक्ष्मजीव-विज्ञान विभाग, पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, कुटुलिया-486001, रीवा, मध्य प्रदेश, भारत

देश के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों द्वारा वर्ष 2021 के दौरान अधिसूचित की गई 21 किस्में

किसानों को कम लागत में ज्यादा मुनाफा दिला सकतीं हैं सोयाबीन की 21 विकसित किस्में

भोपाल। संवाददाता

प्रदेश में सोयाबीन की बुआई का कार्य शुरू हो चुका है। किसान अच्छी पैदावार और अच्छी आमदनी कराने देने वाले बीज की तलाश कर रहा है। प्रत्येक वर्ष देश के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों द्वारा सोयाबीन की नई किस्में तैयार की जाती हैं ताकि किसान कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें। सोयाबीन की नई किस्म के बीज पिछले वर्ष 2021 के दौरान अधिसूचित की गई हैं। किसान इन किस्मों की विशेषताओं एवं क्षेत्र के अनुसार इन किस्मों का चयन कर इसकी बुआई कर सकते हैं। देश के मध्य क्षेत्र जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का बुन्देलखंड भाग, राजस्थान, गुजरात, उतर-पश्चिम, महाराष्ट्र क्षेत्र के लिए पिछले वर्ष जो किस्म विकसित की गई हैं वो इस प्रकार है।

एमएसीएस-1520- सोयाबीन की यह किस्म 98 से 102 दिनों में पक कर तैयार हो जाती है। इस किस्म से 29 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से पैदावार प्राप्त की जा सकती है। एमएसीएस1520 किस्म चारकोल रॉट, पीला, मोजका वायरस बैक्टीरियल पक्षूल, रायजोक्टोनिया, एरियल ब्लाईट तथा अल्टरनरिया लीफ स्पांटा जैसे रोगों के लिए प्रतिरोधकता है। साथ ही तना मक्खी, चक्र भृंग एवं पर्णभक्षी कीट समूह, लीफ हॉपर, स्टिक बग, बीन बग तथा फली छेदक कीट के लिए अत्यधिक प्रतिरोधक है।

एनआरसी-130- सोयाबीन की यह किस्म सीमित वृद्धि करने वाली है। यह किस्म 92 दिनों में पक कर तैयार हो जाती है। सोयाबीन की यह किस्म चारकोल रॉट, टारगेट लीफ स्पांट एवं पांड ब्लाइट के प्रति रोग प्रतिरोधक है। सोयाबीन की इस किस्म से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की पैदावार प्राप्त की जा सकती है। **आरएससी 10-46**- सोयाबीन की यह किस्म 98 से 107 दिनों में पक कर तैयार हो जाती है। यह चारकोल रॉट, पीला मोजाइक वायरस, ब्लाईट, बैक्टीरियल पक्षूल, लीफ स्पांट के साथ-साथ तना छेदक एवं पर्णभक्षी कीटों के लिए प्रतिरोधक है। सोयाबीन की इस किस्म से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की पैदावार प्राप्त की जा सकती है।

आरएससी 10-52- सोयाबीन की यह किस्म 99 से 103 दिनों में पक कर तैयार हो जाती है। यह किस्म बड ब्लाईट, बैक्टीरियल पक्षूल, टारगेट लीफ स्पाट, चारकोल रॉट एवं तना छेदक के प्रति प्रतिरोधक है। इसके साथ ही रायजोक्टोनिया एरियल ब्लाईट एवं पत्ती खाने वाले कीटों के लिए प्रतिरोधी है। सोयाबीन की इस किस्म से 26 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की पैदावार प्राप्त की जा सकती है।

एएमएसएएमबी 5-18- सोयाबीन की यह किस्म 98 से 102 दिनों में पक कर तैयार हो जाती है। यह चारकोल रॉट के लिए प्रतिरोधी है। इसके अलावा पीला मोजाइक वायरस, सोयाबीन मोजाइक वायरस, बैक्टीरियल पश्लूल, रायजोक्टोनिया एरियल ब्लाईट तथा अल्टरनेरिया लीफ स्पांट के लिए मध्यम प्रतिरोधक है। इस किस्म से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की पैदावार प्राप्त की जा सकती है। देश के पूर्वी क्षेत्र (छत्तीसगढ़, झारखण्ड, बिहार, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल) एवं उत्तर-पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र असम, मेघालय, मणीपुर, नागालैंड व सिक्कम क्षेत्र के लिए पिछले वर्ष जो किस्म विकसित की गई हैं वो इस प्रकार है।

एमएएसीएस-1407- सोयाबीन की यह किस्म 99 से 107 दिनों में पक कर तैयार हो जाती है। यह किस्म पीला मोजाइक वायरस, बैक्टीरियल लीफ ब्लाईट, रायझोक्टोनिया एरियल ब्लाईट, पाँड ब्लाईट के लिए प्रतिरोधी है। इस किस्म से 32 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की पैदावार प्राप्त की जा सकती है।

एमएसीएस-1460- सोयाबीन की यह किस्म 93 से 98 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। यह किस्म को सिमित वृद्धि के लिए जाना जाता है। यह पीला मोजाइक वायरस, बैक्टीरियल लीफ ब्लाईट, रायझोक्टोनिया एरियल ब्लाईट, पाँड ब्लाईट के लिए प्रतिरोधी है। तना मक्खी, पत्ती खाने वाले कीट एवं एफिड के लिए मध्यम प्रतिरोधी है। सोयाबीन की इस किस्म से 27 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की पैदावार प्राप्त की जा सकती है।

एनआरसी-132- सोयाबीन की यह किस्म 98 दिनों में पक कर तैयार हो जाती है। यह भारत की प्रथम लिपोक्सीजिनेज 2 मुक्त सोयाबीन प्रजाति है। यह किस्म पर्पल सीड स्टाइन के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी तथा पाँड ब्लाइट के लिए प्रतिरोधी है। तम्बाकू की इल्ली, चक्र भृंग एवं सेमीलूपर के लिए प्रतिरोधी है। सोयाबीन की इस किस्म से 23 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की पैदावार प्राप्त की जा सकती है।

एनआरसी-147- सोयाबीन की यह किस्म 100-106 दिनों में तैयार हो जाती है। यह प्रजाति भारत की प्रथम अत्यधिक ओलिक अम्ल युक्त (42 प्रतिशत) सोयाबीन किस्म है। इस किस्म की पहचान अर्धङ्कसीमित नुकीली अंडाकार पत्तियां, बैंगनी फूल, गहरी भूरी नाभिक होता है। सोयाबीन की यह किस्म ब्लाइट, फली छेदक, चक्र भृंग एवं तना सुरंगक कीटों के लिए प्रतिरोधी है। सोयाबीन की इस किस्म से 21 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की पैदावार प्राप्त की जा सकती है।

एनआरसी-128- सोयाबीन की यह किस्म 105 दिनों में तैयार हो जाती है। मूंग पीला मोजाइक वायरस की प्रतिरोधी तथा चारकोल, रॉट के लिए मध्यम प्रतिरोधी है। इसके साथ ही जल-भराव के लिए सहनशील किस्म है। सोयाबीन की इस किस्म से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की पैदावार प्राप्त की जा सकती है।

एनआरसी-136- सोयाबीन की यह प्रजाति 107 दिनों में तैयार हो जाती है। इंडियन बड ब्लाइट के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी एवं पत्ती खाने वाले कीटों के लिए माध्यम प्रतिरोधी है। सोयाबीन की इस किस्म से 31 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की पैदावार प्राप्त की जा सकती है।

एनआरसीएसएल -1- सोयाबीन की यह प्रजाति 107 दिनों में पक कर तैयार हो जाती है। पीला मोजाइक वायरस तथा पोड ब्लाइट के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी है। चारकोल रॉट, ब्राउन स्पांट, पर्पल सीड स्पाट, अल्टरनरिया लीफ स्पाट, बैक्टीरियल पक्षूल, सोयाबीन मोजाइक वायरस प्रतिरोधी एवं पत्ती खाने वाले कीटों के लिए सहनशील किस्म है। सोयाबीन की इस किस्म से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की पैदावार प्राप्त की जा सकती है।

आरएससी-11-07- सोयाबीन के इस किस्म कि परिपक्वता अवधि 102 दिनों की है। बड ब्लाइट, बैक्टीरियल पक्षूल, टारगेट लीफ स्पाट, चारकोल रॉट, एवं तना मक्खी के लिए प्रतिरोधी तथा रायजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट के लिए मध्यम प्रतिरोधी है। तना छेदक, पर्ण भक्षी कीटों की प्रतिरोधी किस्म है। सोयाबीन की इस किस्म से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की पैदावार प्राप्त की जा सकती है।

आरएससी-10-46- सोयाबीन की इस किस्म की परिपक्वता अवधि 98-103 दिन है। अर्ध-सीमित वृद्धि, बैंगनी फूल तथा काली नाभिक इस किस्म की पहचान है। यह किस्म पीला मोजाइक वायरस, चारकोल रॉट, ब्लाइट, बैक्टीरियल पक्षूल, लीफ स्पांट के साथ-साथ तना छेदक एवं पर्णभक्षी कीटों के लिए प्रतिरोधक है। सोयाबीन की इस किस्म से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की पैदावार प्राप्त की जा सकती है।

एएमएस 2014-1- सोयाबीन की यह किस्म 100 से 105 दिनों में पक कर तैयार हो जाती है। इंडियन बड ब्लाइट, बैक्टीरियल पक्षूल, बैक्टीरियल ब्लाइट, अल्टरनरिया लीफ स्पांट, चारकोल रॉट के लिए प्रतिरोधी तथा अन्य जैविक कारक जैसे पाँड ब्लाइट, रायजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट के लिए मध्यम प्रतिरोधी है। तना मक्खी चक्र भृंग के लिए मध्यम प्रतिरोधी है।सोयाबीन की इस किस्म से 24 से 32 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की पैदावार प्राप्त की जा सकती है।

एपीसी की बैठक में कलेक्टर व अधिकारियों ने तैयार की रणनीति

शहडोल के किसान अब करेंगे स्ट्रॉबेरी किनोवा व गुलाब की खेती

गोपाल दास बंसल, शहडोल।

जिले में अब गेंदा, स्ट्रॉबेरी, गुलाब, किनोवा, टमाटर और लेमन ग्रास की खेती का नवाचार किया जाएगा। कलेक्ट्रेट में आयोजित एपीसी की बैठक में कलेक्टर व अधिकारियों ने रणनीति तैयार की। कलेक्टर ने कहा कि खेती के लिए कृषि विभाग के अधिकारी तथा मैदानी अमला किसानों को प्रेरित करें। कृषि विभाग का अमला किसानों को घर-घर जाकर कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दें तथा इनकी खेती से होने वाले लाभ के संबंध में किसानों को जानकारी दें। जिससे जिले को प्रदेश स्तर में अग्रणी बनाया जा सकें। इस दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों को गेंदा और गुलाब की खेती के लिए ज्यादा प्रोत्साहित करें, जिसके कारण कृषक बाजार में फूलों की बिक्री कर अधिक से अधिक आय अर्जित कर सकेंगे। गेंदे की पत्तियों से मेडिसिन तैयार होती है, इसलिए गेंदे की पत्तियां आसानी से बाजार में बिक सकता है, जिससे किसानों को दोगुना लाभ अर्जित होगा। गेंदा एवं गुलाब की खेती के लिए किसान व जगह चिन्हित करने के निर्देश बैठक में कलेक्टर ने गेंदा एवं गुलाब की खेती के लिए किसान व जगह चिन्हित करने के निर्देश उपसंचालक कृषि को दिए। कलेक्टर ने कहा कि हमारा नवाचार एक सार्थक प्रयास होगा।

टमाटर की खेती भी अधिक से अधिक करवाया जाए

कलेक्टर ने कहा कि टमाटर की खेती भी अपने जिले में किसानों के द्वारा अधिक से अधिक करवाया जाए, जिससे महिला स्व-सहायता समूह के माध्यम से टोमेटो कैचप के लिए प्लांट डाल सकें। इससे भी किसानों एवं महिला स्व सहायता समूह के सदस्यों की आमदनी में इजाफा हो सकेगा। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत हल्दी उत्पादन की भी समीक्षा की तथा सहायक संचालक उद्यान को निर्देशित किया कि अधिक से अधिक मात्रा में हल्दी का उत्पादन किया जाए। इन्हें विक्रय करने के लिए प्रक्रिया की जाएं।

प्राकृतिक कृषि आधारित खेती पर प्रशिक्षण

प्राकृतिक खेती करें किसान, आने वाला समय इसी का है

धनंजय तिवारी, रीवा।

जिले में योजनाबद्ध तरीके से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर फसल विविधीकरण करते हुए किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से कलेक्टर मनोज पुष्प के निर्देश पर प्राकृतिक खेती पोर्टल में पंजीकृत कृषकों की प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गयी। कार्यशाला में वैज्ञानिकों द्वारा प्राकृतिक खेती के तरीकों के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत स्वप्निल वानखेड़े ने कहा कि मध्यम व बड़े किसान अपने कृषि भूमि में से कुछ भूमि में प्राकृतिक खेती करें क्योंकि भविष्य की जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए यह खेती उपयोगी होगी तथा आने वाले समय में इससे ज्यादा मुनाफा होगा। उन्होंने कहा कि धान, गेंहू के साथ-साथ मोटे अनाजों का उत्पादन करें इनसे जहां एक ओर आमदनी के साधन बढ़ेंगे वहीं दूसरी ओर यह उपज स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। उन्होंने कहा कि खेती में परिवर्तन आवश्यक है इससे आने वाली पीढ़ी को लाभ मिलेगा।

ई-कामसज़ के माध्यम से बाजार उपलब्धता की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी

महाप्रबंध यूबी तिवारी ने कहा कि प्राकृतिक खेती से किसानों को लाभ मिले, उनके उपज की ब्रांडिंग हो तथा गुणवत्तापूणज़ पैकिंग व्यवस्था के साथ उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके। उन्होंने मोटे अनाजों जैसे कोदों-कुटकी की फूह प्रोसेसिंग करने तथा अन्य उत्पादों की ई-कामसज़ के माध्यम से बाजार उपलब्धता की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। कृषि वैज्ञानिक बृजेश तिवारी एवं स्मिता सिंह ने प्राकृतिक खेती के प्रमुख बिन्दुओं पर कृषकों से विस्तृत चर्चा की। डॉ. केवल सिंह बघेल ने फ़सलों में कीट प्रबंधन के बारे में बताया। कृषि वैज्ञानिक डॉ. राजेश सिंह ने फ़सल विविधीकरण अन्तर्गत स्ट्राबेरी खेती के साथ फसल प्राणाली अन्तगज़त आलू, प्याज, धनिया एवं भिण्डी आदि की फसल से अधिकतम आय प्राप्त करने की समझाइश दी।

अगले 5 साल में दिखाई देगे 28.3 लाख हेक्टेयर भूमि में विशाल जंगल

8 साल में 36 लाख हेक्टेयर बिगड़ा वन क्षेत्र सुधार देगा वन विभाग

भोपाल। संवाददाता

प्रदेश का 36 लाख हेक्टेयर बिगड़ा वन क्षेत्र आगामी 8 वर्ष में संवर जाएगा। यह बीड़ा उठाया है मप्र वन विभाग ने। तय समय सीमा में कार्य पूरा करने के लिये विभाग द्वारा आगामी वर्षों में करीब ड़ेढ़ लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सालाना पौध रोपण की योजना बनाई है। दरअसल बॉन चैलेंज के तहत 2030 तक भारत 2 करोड़ 60 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि को ठीक करेगा है। पहले चरण में मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, नागालैंड, हरियाणा और कनाज़्टक को शामिल किया गया है। इसमें मप्र में स्थित बिगड़े वनों का 28.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र भी शामिल है। जिसे वर्ष 2030 तक संवरे वनों की श्रेणी में लाने का प्रयास शुरू किया गया है। इसके तहत वन समितियों के सहयोग से करीब 4.31 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की तस्वीर बदली जा चुकी है। यही वजह है कि बीते दो वर्षों में वन क्षेत्रफ ल का रकवा बढ़ा है। भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट इसकी पुष्टि करती है। क्योंकि 2019 में मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र 77,482 वर्ग किमी था। यह 2021 में बढ़कर 77,493 वर्ग किमी हो गया है।

जमीन घटी पर बढ़ा वन क्षेत्र

बीते 2005 साल से वन विभाग की भूमि जहां लगातार कम हुई है, वहीं दूसरी ओर वन क्षेत्र बढ़ा है। आंकलन इसी से किया जा सकता है कि प्रदेश की करीब साढ़े तीन लाख हेक्टेयर भूमि चली गई है। जिसमें 3 लाख 14 हजार हेक्टेयर भूमि वनाधिकार कानून और अतिक्रमण में चली गई है। जबकि 1 लाख 71 हजार भूमि विभिन्न विकास कायोज़ं के लिये प्रदान की गई। बावजूद इसके भारतीय वन सवेज़्क्षण की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में एक लाख 48 हजार हेक्टयेर वन क्षेत्र बढ़ा है।

क्या है बॉन चैलेंज| करीब दस साल पहले कई देशों के प्रतिनिधि जर्मन शहर बॉन में मिले थे। इस बैठक में काटे गए जंगलों को फ़िर पुर्नस्थापित करने का संकल्प लिया गया। लिहाजा इसे बॉन चैलेंज नाम से जाना जाता है। यही कारण है कि यूएनओ द्वारा वन पुर्नस्थापना दशक चलाया जा रहा है।

हर साल औसतन रोपे जाते हैं 5 करोड़ पौधे

प्रदेश में औसतन 5 करोड़ पौधे रोपित होते हैं। वन विभाग और वन विकास निगम के संयुक्त तत्वाधान में यह किया जाता है। यदि बात 2016-17 से 20-21 के बीच 32.72 लाख पौधे रोपे गये हैं। इनमें 2016-17 में 6.40 लाख, 2017-18 में 7.41 लाख, 2018-19 में 7.07 लाख, 2019-20 में 6.27 लाख और 2020-21 में 5.55 लाख पौधे लगाये गए हैं।

हर साल पांच करोड़ पौधे लगाते हैं। एक लाख हेक्टेयर क्षेत्र को संवधिज़्त करते हैं। इसे अब डेढ़ लाख तक पहुंचाना है। पूरी उम्मीद है कि हम अपने लक्ष्य को पूरा कर लेंगे।
चितरंजन त्यागी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत किसानों दिया जा रहा बढ़ावा

एग्री स्टार्टअप के लिए मिलता है 25 लाख तक का फंड

नई दिल्ली

किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं संचालित की जा रहीं हैं। इसी कड़ी में सरकार द्वारा किसानों के बीच रोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए स्टार्टअप को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत नवाचार और कृषि उद्यमिता विकास कार्यक्रम शुरू किया किया गया है। इस योजना के माध्यम कृषि क्षेत्रों में नई तकनीकों और रोजगार को बढ़ावा देना है। ये स्टार्ट-अप्स विभिन्न श्रेणियों जैसे कृषि प्रसंस्करण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल कृषि, कृषि यंत्रीकरण, वेस्ट टू वेल्थ, डेयरी, मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों में स्थापित किए जा सकते हैं।

स्टार्टअप के लिए दिए जाते हैं इतने फंड- किसानों के बीच स्टार्टअप को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए एग्रीप्रेन्योरशिप ओरिएंटेशन के तहत - 2 माह की अवधि के लिए 10,000 रुपये प्रति माह वजीफा दिया जाता है। वित्तीय, तकनीकी, आईपी मुद्दों आदि पर मेंटरशिप प्रदान की जाती है। वहीं आर-एबीआई इनक्यूबेट्स की सीड स्टेज के फंडिग पर 25 लाख रुपये दिए जाते हैं। (85प्रतिशत अनुदान और 15प्रतिशत अंशदान इंक्यूबेट से) एग्रीप्रेन्योर्स की आइडिया और प्री-सीड स्टेज फंडिंग 5 लाख रुपए दिए जाते हैं (90प्रतिशत अनुदार और 10प्रतिशत योगदान इन्क्यूबेट से)।

किस आधार पर होता है लाभार्थियों का चयन

संस्थान के द्वारा अपने कार्यक्रमों के लिए आवेदन करने और विभिन्न चरणों के माध्यम से चयन की कठोर प्रक्रिया अपनाकर और दो महीने के प्रशिक्षण के आधार पर, अनुदान-सहायता के माध्यम से वित्तपोषित किए जाने वाले स्टार्ट-अप्स की अंतिम सूची को अंतिम रूप प्रदान किया जाता है. तकनीकी, वित्त, बौद्धिक संपदा, सांविधिक अनुपालन मुद्दों आदि पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ये माइलस्टोन और समयसीमा की निगरानी के माध्यम से स्टार्ट-अप्स को मेंटरशिप प्रदान करना कार्यक्रम का हिस्सा है।

कहां करें आवेदन इसके लिए आंवटित राशि किस्तों में लाभार्थियों को जारी किए जाएंगे। इन स्टार्ट-अप्स को भारत भर में फैले 29 प्रतिशत व्यवसाय इनक्यूबेशन केंद्रों (केपीएस और आरएबीआइ) में दो महीने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इन स्टार्ट-अप्स के द्वारा युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा वे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसानों के लिए अवसर प्रदान करके आय बढ़ाने में योगदान देंगे। इस योजना के बारे में अधिक जानकारी और अप्लाई करने के लिए https://rkvy.nic.in/ पर विजिट करें।

7 से 9 मिनट में एक एकड़ खेत में किया जा सकता है दवा का छिड़काव

किसान ड्रोन की खरीद पर मिलेगी 75 फीसदी तक की सब्सिडी

भोपाल। संवाददाता

किसानों के हित के लिए सरकार की तरफसे ड्रोन योजना चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से मात्र सात से नौ मिनट में एक एकड़ (0.40 हेक्टेयर) खेत में दवा का छिड़काव किया जा सकता है। इससे किसानों के वक्त और श्रम दोनों की बचत होगी। सरकार की तरफसे किसान ड्रोन की खरीद पर 75 फीसदी तक की सब्सिडी देने की घोषणा की गई है।

5 लाख रुपये की दी जाएगी सब्सिडी

कृषि मंत्रालय की तरफसे हाल ही में की घोषणा में कहा गया कि किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार एससी-एसटी, छोटे और सीमांत, महिलाओं और पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों को ड्रोन खरीदने के लिए 50प्रतिशत या अधिकतम 5 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान कर रही है। इसके साथ ही अन्य किसानों के लिए 40 प्रतिशत या अधिकतम 4 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। सरकार किसानों की सुविधा, लागत कम करने और आय बढ़ाने के लिए ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है।

नियम और शर्तें

- ऐसी जगह जहां हाईटेंशन लाइन या मोबाइल टावर हो, वहां अनुमति जरूरी।
- ग्रीन जोन के क्षेत्र में दवाई छिड़काव नहीं कर सकेंगे।
- रहवासी क्षेत्र के आसपास खेत होने पर भी अनुमति जरूरी।
- खराब मौसम या तेज हवा में नहीं उड़ा सकेंगे।

कृषि विज्ञान केंद्रों में मिलेगा ड्रोन

सरकार की तरफसे लगभग दस लाख रुपये लागत वाले ड्रोन को कृषि विज्ञान केंद्रों पर नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा किसान, कृषक उत्पादक समूह, महिलाएं या किसान महिला समूह स्टार्टअप के लिए भी इसे अपना सकेंगे। अन्य व्यक्ति भी अगर इसे रोजगार के रूप में अपनाना चाहे, तो उसे सरकार सब्सिडी प्रदान करेगी।

ड्रोन चलाने के लिए मिलेगी ट्रेनिंग

सरकार के द्वारा किसानों को ड्रोन के चलाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि महाविद्यालयों में नि:शुल्क प्रशिषण दिया जाएगा।

किसान उत्पादक संगठनों को मिलेगी 75प्रतिशत सब्सिडी

कृषि में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए और इस क्षेत्र के किसानों और अन्य हितधारकों के लिए ड्रोन तकनीक को सस्ता बनाने के लिए, कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन के तहत मान्यता प्राप्त कृषि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या कृषि विज्ञान केंद्र को 100 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। किसान उत्पादक संगठनों को किसानों के खेतों पर दवा के छिड़काव के लिए ड्रोन की खरीद के लिए 75प्रतिशत की दर से सब्सिडी प्रदान की जा रही है।

खरीफ फसलों के बीज की सरकार ने तय किया दर, किसानों को मिलेगा फायदा

सरकार किसानों को अनुदान पर देगी प्रमाणित बीज सोयाबीन बीज पर मिलेगा 2000 रुपये का अनुदान

भोपाल। संवाददाता

मध्य प्रदेश में 15 जून के बाद खरीफ फसलों की बोवनी का काम शुरू हो जाएगा। राज्य सरकार ने 25 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज का इंतजाम भी कर लिया है। साथ ही किसानों को सहकारी समिति और बीज संघ के माध्यम से दिए जाने वाले बीजों की दर भी तय कर दी है। सोयाबीन का प्रमाणित बीज 8100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से दिया जाएगा। इस पर 2000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इसी तरह सुगंधित धान के बीज की दर 3100 रुपये प्रति क्विंटल और अरहर (तुअर) के बीज की दर 4500 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है। इसके साथ ही सरकार ने किसानों से बीज खरीदने की दर भी तय कर दी है।

अधिकतम 30 प्रतिशत बीज नकद में बेच सकती हैं बीज संस्थाएं - अपर मुख्य सचिव (कृषि) अजीत केसरी ने बताया कि किसानों को जो भी बीज नकद में दिया जाएगा, उसे ऋण पुस्तिका में दजऱ् करना होगा। बीज संस्थाएं अधिकतम 30 प्रतिशत बीज नकद में बेच सकती हैं। प्रदेश के किसानों को ही बीज वितरण करने पर अनुदान की पात्रता मिलेगी। किसानों को बीज विक्रय करने की दर तय करने के साथ ही पंजीकृत किसानों से प्रमाणित बीज खरीदने की दर भी तय कर दी गई है। सोयाबीन का बीज 7500, तिल 9100, रामतिल 6950, मूंगफली छिलकायुक्त 5600, धान सुगंधित 2600, धान मोटा 2000, धान पतला 2500, मक्का 2000 , मक्का हाइब्रिड 9000 , ज्वार 2500, कोदो 2500 , मूंग 7300, उड़द 6450 और अरहर का प्रति क्विंटल प्रमाणित बीज 6,400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से उपार्जित किया जाएगा।

जैविक बीज की दर रुपये में (प्रति क्विंटल व अनुदान)

धान	3,600	2,000
मक्का	2,100	3,000
कोदो	4,650	3,000
कुटकी	4,650	3,000
अरहर	4,700	5,000

किसानों के खाते में जमा होगा अनुदान

कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बीज अनुदान की राशि सीधे किसानों के खाते में जमा कराई जाएगी। किसी भी बीज वितरण संस्था को किसानों को भुगतान करने के लिए अनुदान की राशि नहीं दी जाएगी।

फसल	बीज दर (प्रति क्विंटल)	अनुदान (रुपये)
सोयाबीन	8,100	2,000
तिल	8,800	4,000
रामतिल	6,600	4,000
मूंगफली	4,200	4,000
धान सुगंधित	4,100	1,000
धान मोटी	2,500	2,000
धान पतली	3,000	2,000
मक्का	1,600	3,000
मक्का हाइब्रिड	8,700	3,000
ज्वार	2,800	3,000
कोदो	2,500	3,000
कुटकी	4,500	5,000
मूंग	5,400	5,000
उड़द	4,500	5,000
अरहर	4,500	5,000

देश के कुल गेहूं निर्यात का 40.66 प्रतिशत अपने प्रदेश से

भारत से गेहूं निर्यात में मप्र बना नंबर-वन, गुजरात दूसरे स्थान

भोपाल। संवाददाताभोपाल।

मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक विकास नरवाल की मेहनत रंग लाई लगभग 60,00,000 क्विंटल गेहूं विभिन्न देशों में निर्यात कर मध्य प्रदेश का मान बढ़ाया। व्हीट एम.पी. को एक ब्रांड के रूप में स्थापित करने में महती भूमिका निभाई। मध्यप्रदेश शासन द्वारा गेहूं निर्यात की नोडल एजेंसी मंडी बोर्ड को बनाने के बाद प्रबंध संचालक विकास नरवाल द्वारा अपनी कुशल रणनीति के साथ अपने अधिकारी कर्मचारियों के सहयोग से गेहूं निर्यात में मध्य प्रदेश का स्थान पूरे राष्ट्र में पहले नंबर पर स्थापित किया है। निर्यात नीति लागू होने के उपरांत भारत से कुल निर्यात लगभग 1.50 करोड़ क्विंटल गेहू निर्यात हुआ, जिसमें सर्वाधिक लगभग 60.00 लाख क्विंटल गेहू निर्यात किया, जो की कुल निर्यात का 40.66 प्रतिशत है। लगभग 41 लाख क्विंटल गेहू निर्यात कर गुजरात दूसरे स्थान पर है। गुजरात से निर्यात किये गए गेहूं की मात्रा में एक बड़ा भाग मध्य प्रदेश में उत्पाादित गेहूं का है। तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल उसके बाद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थाान, हरियाणा, पंजाब आदि राज्य हैं।

माननीय मुख्यथमंत्री शिवराज सिंह जी के आदेशानुसार मध्यम प्रदेश निर्यात प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी श्री नरवाल द्वारा लगातार अपनी कड़ी मेहनत से गेहूं नियाज़्त को एक मिशन के रूप में लेकर कार्य किया, हर स्तर पर अपनी बुद्धिमता का परिचय देते हुए विभिन्न राष्ट्रों के प्रतिनिधियों से सामंजस्य स्थापित कर विभिन्न एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों से सतत बैठक कर उनसे जीवांत संपर्क स्थापित कर निर्यात की कार्रवाई को अग्रणी बनाया है, जिसमें रेलवे के साथ मंग विशिष्ट रूप से योजना तथा रणनीति बनाकर गेहूं निर्यात को अंजाम दिया है। मध्य प्रदेश में तत्काल निर्यात के लिए प्रोत्साहन नीति को लागू किया, मध्य प्रदेश के लगभग 2000 व्यापारियों को निर्यातक के रूप में पंजीबद्ध किया गया, ई-अनुज्ञा पोटज़्ल को निर्यात की विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए सुदृढ़ किया तथा मंडी बोर्ड में निर्यात सेल को स्थापित कर समस्त अधिकारी कमज़्चारियों को निर्यात की कार्रवाई में संलग्न किया गया, जिसमें मुख्य रुप से अपर कलेक्टर/अपर संचालक डीके नागेंद्र, अपर संचालक चंद्रशेखर वशिष्ठव, सहायक संचालक पीयूष शर्मा, स.उ.नि. दीपक गोयल की महती भूमिका रही है।

मंडी बोर्ड के सात संभागों में भोपाल संभाग द्वारा उत्कृलष्टम प्रदर्शन करते हुए सर्वाधिक लगभग 41 लाख क्विंटल गेहू का निर्यात भोपल संभाग की मंडियों से किया गया, उक्ता उत्कृष्ट प्रदर्शन में भोपाल संभग की संयुक्त संचालक रितु चौहान की महती भूमिका रही। गेहू निर्यात की कार्यवाही में संलग्न समस्तर मंडी सचिवों, आंचलिक अधिकारियों मंडी के व्यारपारी भाईयों, निर्यातकों तथा मंडी के समस्त अधिकारीयों/कर्मचारियों अन्य सहभागियों का प्रबंध संचालक द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया है।

18 जुलाई के बाद आएगी किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र देने की लिस्ट

भोपाल। 25 मई 2022 से मध्यप्रदेश के कृषि विभाग द्वारा किसानों को बुआई हेतु आवश्यक कृषि यंत्र अनुदान पर उपलब्ध कराने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। जिसका 6 जून के दिन अंतिम दिन था, परंतु राज्य में पंचायत चुनाव के चलते 28 मई से ही आचार संहिता लागू हो गई है। ऐसे में कृषि अभियांत्रिकी संचनालय द्वारा अभी लॉटरी जारी नहीं की जाएगी। सामान्यत: आवेदन समाप्त होने के पश्चात ही कृषि अभियांत्रिकी विभाग चयनित किसानों की सूचि जारी कर देता है। जिसमें चुनाव के चलते अब देरी हो सकती है।

आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

जागत गांव हमार

कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला, जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए।

संपर्क करें

जबलपुर, प्रवीण नामदेव-9300034195
शहडोल, राम नरेश वर्मा-9131886277
नरसिंहपुर, प्रहलाद कौरव-9926569304
विदिशा, अवधेश दुबे- 9425148554
सागर, अनिल दुबे-9826021098
राहतगढ़, भगवान सिंह प्रजापति-9826948827
दमोह, बंटी शर्मा -9131821040
टीकमगढ़, नीरज जैन -9893583522
राजगढ़, गजराज सिंह मीणा -9981462162
बैतूल, सतीष साहू-8982777449
मुरैना, अवधेश दण्डोतिया -9425128418
शिवपुरी, खेमराज मौर्य-9425762414
भिण्ड- नीरज शर्मा-9826266571
खरगौन, संजय शर्मा-7694897272
सतना, दीपक गौतम-9923800013
रीवा-धनंजय तिवारी-9425080670
रतलाम, अमित निगम-70007141120
झाबुआ-नोमान खान-8770736925

कार्यालय का पता:- लाजपत भवन प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एमपी नगर, जोन-1, भोपाल, मप्र,
संपर्क करें- 07554064144, 9229497393, 9425048589

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **अरविंद मिश्र, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)